राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रसारित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार, ११ दिसंबर २०२० वर्ष-३, अंक -३१२ पृष्ठ-०८ मूल्य-०१रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023 (Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

नए संसद भवन के भूमि पूजन पर पीएम मोदी बोले-भारत के लिए लोकतंत्र में, जीवन मंत्र भी है; जीवन तत्व भी है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के अवसर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह जताया गया था। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता सहित कई तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि पुराने भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पीएम मोदी जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने नई पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। आने वाली पीढ़ियां नए संसद भवन को देखकर गर्व करेंगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करके इसका निर्माण हुआ है।

इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्रियों और कई देशों के राजदूत शामिल हुए हैं। भूमि पूजन के बाद 1:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना हुई। नया संसद भवन कई मायने में खास बनने जा रहा है। इसे बनाने में 900 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे। नए संसद भवन को प्रदूषण मुक्त और पेपरलेस ऑफिस से सुसज्जित किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा आज के दिन को गौरवशाली बताया है।

- पीएम मोदी ने कहा कि वाद-संवाद संसद के भीतर हों या संसद के बाहर, राष्ट्रसेवा का संकल्प, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए।

- पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। पीएम ने कहा कि भारत का लोकतंत्र, सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में, जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और

साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है।

- पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह जताया गया था। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता सहित कई तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा।

- पीएम मोदी ने कहा कि जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने नई पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। आने वाली पीढ़ियां नए संसद भवन को देखकर गर्व करेंगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करके इसका निर्माण हुआ है।

- पीएम मोदी ने कहा कि पुराने भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी।

- भूमि पूजन के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा।

- पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को घड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यहीं हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी।

- पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले, मैंने सिर झुकाकर, माथा टेककर, लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था।

- आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है।

- पीएम मोदी ने कहा है कि हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। और इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा कि जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा, हमारी संसद की नई इमारत बने।

- देश का न्या संसद भवन सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र होगा। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का आभार प्रकट करता हूं- ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर

- दोनों सदनों के सांसदों ने पीएम मोदी से नए संसद भवन के लिए आग्रह किया था। सांसदों की भावना को देखते हुए प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के निर्माण की स्वीकृति दी। इसके लिए मैं पीएम मोदी का आभार प्रकट करता हूं- ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर

- इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद भवन देश की आजादी की साक्षी रहा है। भविष्य में हमारे संवैधिक दायित्यों को पूरा करने के लिए अधिक सांसदों की आवश्यक्ता होगी।

कुतुब मीनार में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा, मांगा पूजा-पाठ का अधिकार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को हिंदुओं और जैनों के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाए जाने का आरोप वाली याचिका पर अदालत में 24 दिसंबर को सुनवाई होगी। अदालत में दाखिल याचिका में वहां पर देवताओं की पुनर्स्थापना करने और हिंदुओं और जैन को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने की मांग की गई है। साकेत स्थित सिविल जज नेहा शर्मा की अदालत में दाखिल वाद में कहा गया है कि 'मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू-जैन मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दिया। इसमें यह भी दावा किया गया कि तोड़े गए मंदिरों के पत्थर एवं निर्मित फूल पत्तियों, हिंदू धर्म के अनुसार नक्काशी किए गए पत्थर एवं मंदिर के अन्य सामानों से मस्जिद बनाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि परिसर में स्थित उस मस्जिद में भगवान विष्णु, गणेश, कमल, स्वास्तिक आदि कई ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो यह साबित करता है कि यह जगह हिंदू मंदिरों का था और उसी को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। अदालत में दाखिल इस याचिका में उस जगह पर देवी-देवताओं को पुनर्स्थापना करने और हिंदुओं और जैन को पूजा -पाठ करने का अधिकार देने की मांग की है। अदालत में यह मुकदमा भगवान विष्णु और पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की ओर से दाखिल किया गया है। अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने याचिका में अदालत से केंद्र सरकार और भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण विभाग को एक ट्रस्ट बनाने का आदेश देने की भी मांग की गई है। अदालत में दाखिल वाद के मुताबिक मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन दिल्ली आते ही सबसे पहले हिंदू के 27 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया जो ग्रहों की गणना के लिए महरौली में बनाए गए थे। महरौली को पहले मिहरावली कहा जाता था। इसमें यह भी कहा गया है कि जल्दी बाजी में मंदिरों को तोड़कर बची हुई सामग्री से ही कुव्वत उल इस्लाम नाम का मस्जिद सन 1192 में बना दिया गया।

कोविड-19-वैक्सीन के बावजूद रहेंगे प्रतिबंध, अगली सर्दियों तक लगाना पड़ सकता है मास्क

नई दिल्ली। कोरोना से लड़ने के लिए ब्रिटेन में लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भले ही शुरू हो गया है लेकिन प्रतिबंधों से उन्हें तत्काल राहत की उम्मीद कम है। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि हम भले ही वैक्सीन लाने वाले पहले देश बन गए हैं और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम लापरवाह न बनें। संभव है कि वैक्सीन के बावजूद अगली सर्दियों में भी ब्रिटेन के लोगों को मास्क लगाना पड़े।

ब्रिटेन की सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पैट्रिक वालेंस के मुताबिक, टीकाकरण के साथ ही अगर लोग सावधानी रखेंगे तो यह उनके लिए और भी बेहतर होगा। इसके साथ ही प्रतिबंध भी लागू रहेंगे, क्योंकि फिलहाल इनका कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले अक्तूबर में भी पैट्रिक वालेंस ने आशंका जताई थी कि कोरोना वायरस वैक्सीन से भी खत्म नहीं होगा और सामान्य फ्लू की तरह ही हर साल इसके संक्रमण के मामले सामने आते रहेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि वैक्सीन लेने से संक्रमण की संभावना कम तो होगी और वायरस की वजह से होने वाली बीमारियों की रफ्तार भी कम हो जाएगी।

क्रिसमस से पहले छूट-ब्रिटेन की सरकार ने एक महीने के लॉकडाउन के बाद क्रिसमस से पहले लोगों को टियर-3 और टियर-4 स्तर के सख्त प्रतिबंधों से थोड़ी राहत दी है। हालांकि, इस दौरान बाजारों में खूब भीड़ हो रही है। खरीदारी करने वाले लोगों की सड़कों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पैनिक शॉपिंग से बचें। लोग सामाजिक दूरी के नियम को भी दरकिनार करते दिख रहे हैं। वहां विपक्षी सांसद प्रतिबंधों को लेकर लंबे समय से जॉनसन सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार जल्द ही नई पाबंदियों की घोषणा कर सकती है।

रूस में भी राहत नहीं-रूस ने स्पूतनिक-1 टीका लगाना शुरू कर दिया है। दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीट्सबर्ग में इस सप्ताह अधिकारियों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। स्थानीय अधिकारियों ने रेस्तरां, कैफे और बार 30 दिसंबर से तीन जनवरी के बीच बंद करने का आदेश दिया है।

म्यांमार सीमा पर उग्रवादी गुटों की मदद कर रही चीनी सेना

यहां भारतीय जवान कर चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक

नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन को लगातार भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। घुसपैठ की हर कोशिश को ना सिर्फ नाकाम किया, बल्कि ड्रैगन की विस्तारवाद की नीति को भारत ने दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अब चीन म्यांमार सीमा पर हथियारबंद उग्रवादी गुटों को चीनी सेना मदद कर रही है। भारतीय एजेंसियों ने चीनी मदद को लेकर अंदरूनी रिपोर्ट में चिंता जताई है। हालांकि, चीन इससे इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि म्यांमार में भारतीय जवान सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं।

अधिकारियों का कहना है कि चीनी सेना उग्रवादी समूहों को हथियारों की आपूर्ति और उन्हें ठिकाने प्रदान करके मदद दे रही है। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से चीन पूर्वोत्तर में एक नया मोर्चा खोल रहा है। सूत्रों का कहना है कि म्यांमार में सशस्त्र समूह को मदद पहुंचाई गई। इन सशस्त्र समूहों में युनाइटेड वा स्टेट आर्मी और अराकान आर्मी शामिल हैं,

जिन्हें इस साल आतंकी संगठन घोषित नामित किया गया है।

विद्रोही नेताओं ने ट्रेनिंग ली-अधिकारियों ने कहा कि कई सुरक्षा एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि भारत के सबसे वांछित विद्रोही नेताओं में से कम से कम चार ट्रेनिंग और हथियारों के लिए मध्य अक्तूबर में चीनी शहर कुनमिंग में गए थे। म्यांमार सीमा के साथ बढ़ी गतिविधियों के मद्देनजर भारत ने इन इलाकों में म्यांमार से संपर्क साधकर सुरक्षा गतिविधियों को बढ़ाया है। एक अधिकारी ने कहा कि विद्रोही समूहों में से कुछ संकट पैदा करने के मकसद से गतिविधि चला रहे हैं, लेकिन हम शांति की बातचीत कर रहे हैं।

दोनों देशों का म्यांमार में निवेश-बता दें भारत और चीन दोनों ही म्यांमार में निवेश कर रहे हैं। चीन, बंगाल की खाड़ी के साथ अपने दक्षिणी प्रांत युन्नान को जोड़ने के लिए गैस पाइप लाइनों और सड़कों में निवेश कर रहा है। इस बीच, भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के लिए 292 लाख अमेरिकी डॉलर की कलादान मल्टीमॉडल परियोजना में निवेश कर रहा है।

दिल्ली में पहली बार 10 डिग्री के नीचे गया पारा, मौसम विभाग की चेतावनी-अभी और बढ़ेगी ठंड

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियां अपना कमाल दिखा रही है, ऐसा कहा जा रहा हा कि दिल्ली में ठंड इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और पारा 0 डिग्री के नीचे भी जा सकता है लेकिन अभी की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को इस मौसम में पहली बार न्यूनतम तापमान 9.4 दर्ज किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरकर 9.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य पारा स्तर से तीन डिग्री कम है, यहां तक कि मौसम विभाग ने कहा कि इस साल की शुरुआत में सर्दी बढ़ रही है। इस बीच, राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत के मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वानुमान लगाया था कि इस सप्ताह ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाएगा क्योंकि बर्फ से ढंके पश्चिमी हिमालय की ओर से हवाएँ चलेगी जो इस तरफ आ रही हैं। पंजाब के आदमपुर और फरीदकोट में गुरुवार को सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस, हिसार, नारनौल, रोहतक, सिरसा में क्रमशः 8.2, 8, 9 और 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान केंद्र के क्षेत्रीय प्रमुख, कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, ÷आमतौर पर, नवंबर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है। हाल के वर्षों में, 2017 में नवंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान, न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। इस समय न्यूनतम तापमान गिरकर एकल अंकों के लिए असामान्य हो गया है। इस साल की शुरुआत में सर्दियों की शुरुआत हो रही है,

मोदी सरकार बदलेगी पीएफ के नियम और काम के घंटे, घटेगी आपकी सैलरी- जानें क्या होंगे नए नियम

नई दिल्ली। अगले साल से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (पीएफ) मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं, हाथ में आने वाला पैसा (टेक होम सैलरी) घटेगा। यहां तक कि कंपिनयों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए तीन मजदूरी संहिता विधेयक (कोड ऑन वेजेज बिल)। इन विधेयकों के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। वेज (मजदूरी) की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलेरी के अधिकतम 50 फीसदी होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।

इसलिए वेतन घटेगा और पीएफ बढ़ेगा-नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50त्न या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों का वेतन संरचनाबदलेगा, क्योंकि वेतन का गैर-भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलेरी के 50 फीसदी से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो जाता है। मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक-होम या हाथ में आने वाला वेतन में कटौती होगी।

रिटायरमेंट की राशि में होगा इजाफा-ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। उच्च-भुगतान वाले अधिकारियों के वेतन संरचना में सबसे अधिक बदलाव आएगा और इसके चलते वो ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी। क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीजों से कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी।

काम के घंटे 12 घंटे करने का प्रस्ताव-नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। ओएसच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने के निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल हैं।

मोदी सरकार के लिए साख का सवाल कृषि कानून, किसान भी अपनी मांगों पर अड़े, कैसे खत्म होगा किसान आंदोलन ?

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। किसानों की मांग पर कल किसान नेताओं को केंद्र सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और तीनों कानूनों के वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहने से सरकार सकते में है। सरकार का मसौदा किसानों की ओर से खारिज किए जाने से सरकार चिंतित भी है। सरकार का मानना है कि किसानों की वाजिब मांगो पर गौर किया गया है और वह कानून में बदलाव करके उनकी चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में उनका विधेयकों को वापस लेने की मांग पर अड़ना ठीक नहीं है।

सरकार का मानना है कि किसानों को यह देखना चाहिए कि उनकी चिंताओं को दूर किया जा रहा है। सरकार ने अपने लिखित प्रस्ताव में एमएसपी समेत नौ मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया है। यह भी कहा है कि वह खुलेमन से हर शंका पर विचार करने को तैयार है। लेकिन किसान जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

सरकार का मानना है कि किसानों को भी सकारात्मक रुख अपनाना होगा। किसानो को कानूनों को वापस लेने की मांगों पर अड़े रहने की बजाय अपनी अन्य चिंताओं का समाधान सरकार से मांगना चाहिए, जिसमें जाहिर है कि सरकार देर नहीं करेगी। जानकार मानते हैं कि सरकार के लिए पूरी तरह से रोलबैक संभव नहीं होगा। क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि विपक्ष को कोई नया मुद्दा खड़ा करने का मौका देना। सरकार के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल किसानों को समझाने की कोशिश जारी रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह खुद कमान संभाल चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने किसान नेताओं से बात की और लिखित प्रस्ताव दिया और आज कृषि मंत्री के साथ बैठक कर ताजा स्थिति की समीक्षा की है।

कृषि सुधार कानूनों को लोगों के बीच लेकर जा सकती है सरकार

इसके अलावा सरकार अपने सुधारों को लोगों के बीच ले जाने की अपनी मुहिम भी तेज कर सकती है। साथ ही कृषि सुधारों के प्रति मिल रहे किसानों एवं अन्य वर्ग के समर्थन को भी सामने लाया जाएगा। फिलहाल किसान संगठनों का रुख कड़ा है। विपक्ष इसे और धार देने में जुटा है। विदेशों में भी इस कानून की चर्चा हो रही है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में सरकार को बहुत सोच समझकर कदम उठाने पड़ेंगे। जानकार मानते हैं कि बातचीत से हल निकालने की कोशिश ही सबसे बेहतर रास्ता होगा। वरना सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

सरकार ने साफ कर दी है मंशा- पीछे नहीं हटेगी

जानकार मानते है कि कृषि सुधारो से जुड़े कानूनों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मुखरता से पैरवी की है उसके बाद पूरी तरह से पीछे हटना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। ये सरकार की साख और नाक का सवाल हो गया है। कुछ जानकार मानते हैं कि भूमि सुधार क़ानून पर भी सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े थे। उस वक्त विपक्ष लामबंद हो गया था। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि किसानों को आगे किस तरह से समर्थन मिलता है। हालांकि एक बात महत्वपूर्ण है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी केंद्र सरकार के साथ नहीं था। लेकिन, इस बार आरएसएस से जुड़े किसान संगठन चाहे वो स्वदेशी जागरण मंच हो या फिर भारतीय किसान संघ कुछ सुधारों के साथ इन कानूनों को किसान के हित में बता रहे हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

बैग का बोझ

स्कूल भले ही बंद हों, लेकिन स्कूली बच्चों को भारी बस्ते से मुक्ति दिलाने के लिए चल रहे प्रयास न केवल सुखद, बल्कि स्वागत के योग्य भी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार, बच्चों का स्कूल बैग उनके अपने वजन का दस प्रतिशत ही होना चाहिए। इसके अलावा कक्षा दो तक के बच्चों को कोई होमवर्क न देने का बहु-प्रतीक्षित निर्देश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल, वर्षों से बच्चों को स्कूली बैग के बोझ से मुक्ति दिलाने की चर्चा चल रही थी। यदा-कदा भलमनसाहत में स्कूल बैग को हल्का करने की सलाह भी दी जाती रही, लेकिन अब चूंकि बाकायदे नीति बनाकर इस अच्छी पहल को लागू करने की कोशिश हो रही है, तो इस पर खासतौर से स्कूल संचालकों को ध्यान देना चाहिए। भारी या हल्के स्कूल बैग कहीं से भी इस बात के संकेत नहीं हैं कि बच्चा पढ़ाकू है या उसके स्कूल में अच्छी या खराब पढ़ाई होती है। विगत दशकों में कुछ दिखावापसंद स्कूलों में लगभग होड़-सी लग गई थी कि किस स्कूल का बैग कितना भारी हो सकता है। कोई शक नहीं, स्कूल में जितने पीरियड नहीं होते, उनसे ज्यादा किताबें, कॉपियां मंगाने को बहुत कम ही लोग गंभीरता से ले रहे थे। इक्का-दुक्का अभिभावक आपत्ति करते भी थे, तो स्कूल के शोर में उनकी आवाज दब जाती थी। देखा-देखी भेड़चाल स्वरूप स्कूलों के बैग बड़े और भारी होते चले गए। पीठ और कंधे पर टांगे या थककर बैग घसीटते बच्चे शहरों में तो आम हो गए। अब जब केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को परिपत्र जारी कर दिया है, तब राज्यों को अपने स्तर पर बच्चों के बैग को हल्का कराने की तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ जगह इसकी शुरुआत सरकारी स्कूलों से भी करनी पड़ सकती है, लेकिन विशेष रूप से निजी स्कूलों को पाबंद करना पड़ेगा। उन्हें समझाना होगा कि वे अपनी समय सारिणी सुधारें, केवल उन्हीं किताबों और कॉपियों को स्कूल मंगवाएं, जिनकी जरूरत है। इसके साथ ही, बच्चों के पाठ्यक्रम को हल्का करने की चर्चा भी हो रही है, तो स्कूलों में पीरियड की संख्या घटाने पर भी विचार करना चाहिए। कुछ स्कूल काफी सारी किताबें और कॉपियां खुद ही रख लेते हैं, तो यह भी एक अच्छा तरीका है, ताकि बच्चों को कम से कम बोझ के साथ स्कूल आना पड़े। अनेक अध्ययनों ने हमें बताया है कि भारी बैग कूबड़ और रीढ़ संबंधी अन्य समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। जब बच्चों के बढ़ने या लंबे होने की उम्र होती है, तब उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ लादना खतरे से खाली नहीं है। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया था कि भारत में 68 प्रतिशत बच्चे हल्के पीठ दर्द से पीड़ित हो सकते हैं और यह दर्द न केवल हमेशा के लिए बना रह सकता है, बल्कि कूबड़ की समस्या भी पैदा कर सकता है। देश के मुख्य शहरों में 2,500 से अधिक बच्चों और 1,000 से अधिक माता-पिता के बीच किए गए अध्ययन में पाया गया कि सात से 13 साल के 88 प्रतिशत से अधिक बच्चे अपने शरीर के वजन का 45 प्रतिशत से अधिक अपनी पीठ पर लादने को मजबूर हैं। देश तो यही चाहेगा कि कोरोना के बाद स्कूल जब भी खुलें, बच्चों को हल्के बैग के साथ तनकर स्कूल जाते देखा जाए।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की सामरिक चुनौतियां

जी. पार्थसारथी

ऐसे समय में जब कोरोना वायरस महामारी संबंधित विषय वस्तु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, इस दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं इस साल में और हुई हैं, जो भारत की विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में आए बड़े बदलाव को परिलक्षित करती हैं। इनमें से एक है, 'क्वाड' नामक गुट में भारत की सक्रिय भागीदारी, यह गठजोड़ चार देशों के बीच सुरक्षा-नीत आपसी सहयोग है। जाहिर है इसके बनने के पीछे कारणों में भारत की सीमाओं को दरपेश खतरे के अलावा हिंद एवं प्रशांत महासागरीय इलाके में चीन से पैदा हुई चुनौतियों का संयुक्त रूप से सामना करना है। इसी बीच चीन ने अप्रैल माह के शुरू में लद्दाख के देपसांग क्षेत्र में बड़ी संख्या में अपने फौजी इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। यह प्रयास दौलत बेग ओल्डी स्थित सामरिक महत्व के भारतीय हवाई अड्डे को खतरा पैदा करने के मंतव्य से है, और इससे आगे, वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा से परे, जम्मू-कश्मीर में काराकोरम दर्रे को पार करने की स्थिति पाना है। दूसरी बड़ी घटना है, पैंगोंग झील क्षेत्र में भारत द्वारा चीनी घुसपैठ के जवाब में आक्रामक प्रतिक्रिया दिखाना, जहां सामरिक महत्व की कुछ चोटियों को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में कर लिया है, इससे पहले यहां कोई काबिज नहीं हुआ था। भारतीय फौज ने बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों और तोपखाने की सहायता से लद्दाख में अग्रिम कार्रवाई करते हुए सैन्य अभियान चलाया और सामरिक चोटियों को अपने नियंत्रण में ले लिया, वहां से चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती पर नजर रखी जा सकती है। यह अभियान पैंगोंग झील से सटे एक बड़े भूभाग में चलाया गया। अब लद्दाख क्षेत्र में जिन चोटियों पर हमारा कब्जा और नियंत्रण बन गया है, वहां से सेना हटाने की सलाह देना एक बड़ी भूल होगी। लद्दाख में हुई इस घटना के अतिरिक्त विदेश मंत्री एस. जयशंकर 6 अक्तूबर को टोक्यो गए थे। कोविड महामारी के बीच हुई यह यात्रा क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने हेतु थी। चार मुल्कों के इस गुट में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस बैठक में जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि क्वाड नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने को प्रतिबद्ध है और समुद्री आवाजाही की आजादी जैसे सिद्धांतों की कद्र करता है, अन्य देशों की क्षेत्रीय सार्वभौमिकता का भी सम्मान करता है और हिंद-महासागरीय क्षेत्र में उपजने वाले किन्हीं विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करने के पक्ष में है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षामंत्री मार्क एस्पर अपने भारतीय समकक्षों से वार्ता करने नयी दिल्ली आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। दोनों मुल्कों ने इस इलाके में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने हेतु उच्चस्तरीय सुरक्षा वार्ता की। भारत ने संवेदनशील सैटेलाइट डाटा साझा करने पर अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण सैन्य संधि की है। अब अमेरिका के सौजन्य से सीमा पार होने वाली चीनी गतिविधियों पर जासूसी सूचनाएं भारत को समय पर मिल सकेंगी, जिससे अग्रिम कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चीन से दरपेश खतरों को लेकर अमेरिकी नजरिए का पता विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 48 पृष्ठीय रिपोर्ट से चलता है, जिसका शीर्षक है: 'चीनी चुनौतियों के अवयव।' इसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे चीन ने मदद के नाम पर एशिया और अफ्रीका के दीगर विकासशील देशों को कर्ज जाल में फांसा है। अब ये मुल्क उधार न चुका पाने की एवज में अपनी जमीन, बंदरगाह और विकास परियोजनाएं चीन को सौंपने को मजबूर हैं। इसकी शुरुआत चीन ने श्रीलंका की हमबनतोता बंदरगाह विकास परियोजना से की थी। इस बंदरगाह में शायद ही किसी जहाज ने लंगर डाला होगा, लेकिन इसको बनाने में उठाया कर्ज चुकता न करने के बदले उक्त सुविधा चीन को सौंपनी पड़ी है। इसी तरह का प्रयास चीन म्यांमार में निवेश करने के बहाने से करना चाहता है, जहां वह बंगाल की खाड़ी में स्थित क्याउक्फयू बंदरगाह के विकास में धन लगाएगा। इसके अलावा वह म्यांमार सरकार पर दबाव बना रहा है कि अन्य कई बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं और औद्योगिक परियोजनाओं का काम उसे सौंपा जाए। ऐसा करके वह सड़क मार्ग से क्याउक्फयू को अपने युन्नान प्रांत से जोड़ना चाहता है। लगता है आन सान सू की और म्यांमार के जनरल इस बारे में चौकस हैं। इसी बीच भारत ने अपने उत्तर-पूर्वी राज्यों की पहुंच म्यांमार की भूमि से होकर बंगाल की खाड़ी तक करने को सित्वे बंदरगाह का विकास किया है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हुई तेज तरक्की के आलोक में हमें ताईवान के साथ मिलकर रक्षा एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जिसमें नये उद्यम भी शामिल हों, इनका विकास करना चाहिए। फिलहाल इस क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण विषयों में भारत की निर्भरता चीन पर बहुत ज्यादा है, जिसे खत्म करना होगा। हुआवई जैसी विशाल कंपनियां चीनी सरकार का सामरिक औजार हैं। 60 खरब डॉलर लागत वाली चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए उठाया कर्ज अंततः पाकिस्तान को भी ग्वादर बंदरगाह और इससे लगती जमीन चीन को सौंपने का कारण बनेगी। यही पैंतरा चीन ने मालदीव में भी लगाना चाहा था। किंतु भारत-अमेरिका के संयुक्त प्रयासों से उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई और मालदीव की तत्कालीन सरकार चुनाव में हार गई। हालांकि चीन ने कर्ज जाल वाला नुक्ता अफ्रीका में भी इस्तेमाल किया है। मुख्य यूरोपियन ताकतें जैसे कि यूके, फ्रांस और जर्मनी आदि अब संयुक्त राष्ट्र मंचों पर चीन को मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर घेरने को आतुर हैं। आगे बहुत कुछ बाइडेन प्रशासन पर निर्भर करेगा कि हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चीन द्वारा श्रेष्ठता बनाने के प्रयासों से निपटने पर वह यूरोपियन सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा या नहीं। चीन के सीमा संबंधी विवाद अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों से हैं, मसलन, जापान, ताईवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई। चीन अपने इन पड़ोसियों के इलाके हड़पता जा रहा है। अरब सागर में भारत-अमेरिका एवं क्वाड सदस्यों का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास दर्शाता है कि भारत चीन के रवैये से आज़िज आए अन्य मुल्कों के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। यूरोप भर में चीन के महत्वाकांक्षी 5-जी संचार ढांचा निर्माण प्रयासों का विरोध हो रहा है। हिमालय में सर्दियों की बर्फ गिरने की शुरुआत होने से चीन के लिए वहां बड़ा सैन्य अभियान चलाना फिलहाल मुश्किल बन गया है लेकिन यहां भूलना नहीं है कि चीन सामरिक इलाके धीरे-धीरे 'कुतर कर शामिल करने' की महारत रखता है। उम्मीद करें कि लद्दाख और अन्य जगहों पर शांति स्थापना और तथाकथित वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने को भारत-चीन कोई हल निकाल पाएंगे। हालांकि इस सीमा रेखा की स्पष्ट निशानदेही कभी नहीं हुई है और घाटे में भारत ही रहा है। तथ्य तो यह है चीन इस कमी का दुरुपयोग करके समय-समय पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करके इलाका हड़पता आया है, चाहे यह लद्दाख हो या सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। यहां तक कि वह भूटान के भूभाग पर भी दावा करता है।

लेखक पूर्व राजनयिक हैं।

आज के ट्वीट

प्रण

हम भारत के लोग, ये प्रण करें- हमारे लिए देशहित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा। हम भारत के लोग, ये प्रण करें- हमारे लिए देश की चिंता, अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी। हम भारत के लोग, ये प्रण करें- हमारे लिए देश की एकता, अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं होगाः PM

ज्ञान गंगा

सेवा धर्म

श्रीराम शर्मा आचार्य

दान सेवा एक ऐसा कार्य है जो लगता तो सामान्य, छोटा और कुछ लोगों की दृष्टि से ओछा भी, पर वस्तुतः वह सही मायने में व्यक्तियों के व्यक्तित्व को सुगढ़ बनाने, परिमार्जित करने और तप तितिक्षा के लिए तैयार करने में आधार का काम करता है। सन्त विनोबा, गांधी जी, मदर टेरेसा आदि पुण्यात्माएं सेवा कार्य को आजीवन करती रहीं। वे समझते थे सेवा की महत्ता को। सेवा कार्य आत्मा की आवश्यकता का पोषण है। उसको निरंतर और निर्बाध गति से करते रहना इसलिए आवश्यक है कि हम जीवित रहें, हमारी आत्मा और उसकी सुरुचि जीवित रहें। किसी पर एहसान करने के लिए, दूसरों के सहायक और उपकारी बनने के लिए, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भी नहीं, यश के लिए भी नहीं। सेवा का प्रयोजन आत्मा की गरिमा को अक्षुण्ण रखने और उसके जीवन साधन जुटाए रखने के लिए है। इसलिए इसे करते रहना चाहिए। ऐसा सोचना उचित नहीं कि मैंने इतना तो कर लिया, क्या अब सदा ही करता रहूंगा? जो सेवा की आवश्यकता और महत्ता को समझता है, उसे उससे कभी भी ऊब नहीं आती। जो ऊबता हो समझना चाहिए, अभी उसे सेवा का रस नहीं आया। जब एक बार उस परम धर्म का रसास्वादन कर लिया जाता है तो उसे छोड़ सकना संभव नहीं होता। फूलों में कैसा रस है, इसे मधुमक्खी जानती है और वह जन्म से लेकर मरण पर्यंत अनवरत रूप से उसी मधुरिमा में निमग्न रहती है। न थकती है, न ऊबती है, और कभी यह नहीं सोचती कि इतना लम्बा समय मधु संचय के प्रयोजन में लग गया, अब कोई धंधा ढूंढ़ेंगे, विश्राम करेंगे। वह ऐसा इसलिए नहीं सोच सकती कि उसकी अंतरात्मा उस क्रियाकलाप की गरिमा को समझी ही नहीं, स्वीकार भी कर चुकी है। भ्रमर का आशय और कहां है? पराग से विमुख होकर वह और क्या खोजे? तितली को अपने सौन्दर्य के समतुल्य पुष्प के अतिरिक्त और कुछ दीखता ही नहीं। आखिर, वह जाए भी कहां? बैठे भी कहां? करे भी तो क्या? जिनका दृष्टिकोण उत्कृष्टता का अभ्यस्त हो गया, उन्हें निकृष्टता की दुर्गन्ध में श्वास ले सकना संभव भी नहीं है। सेवा धर्म छोड़कर अन्यत्र आत्मा की गरिमा के अतिरिक्त और कोई कार्य है भी तो नहीं।

लड़कियों की शिक्षा पर कहर बन टूटा कोरोना

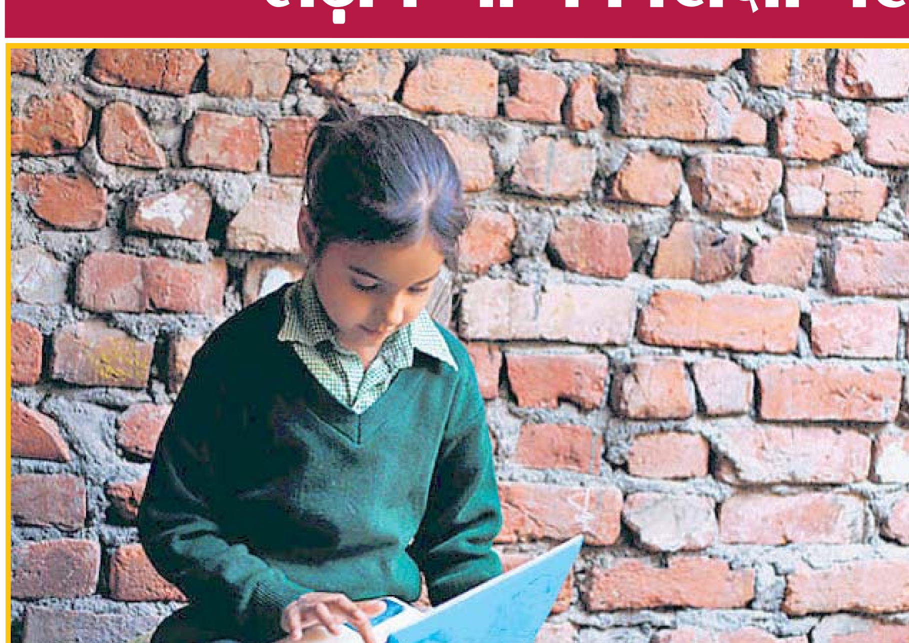

अरुण कुमार कैहरबा

कोरोना महामारी के प्रत्येक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के आखिरी पड़ाव में मार्च महीने में स्कूल बंद हुए थे। आज तक सही प्रकार से स्कूल खुलने की राह नहीं निकली है। बीच में हरियाणा सहित कुछ राज्यों में नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए। कुछ राज्य स्कूल खोलने की तैयारियां कर रहे थे लेकिन कोरोना के बढ़ते केसों ने सारी योजनाओं को चौपट कर दिया। 2020-21 के सत्र में तो पहली से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए एक भी दिन स्कूल नहीं खुला है। नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थी भी कुल मिलाकर मार्गदर्शन आदि लेने के लिए स्कूलों में गए हैं। अध्यापकों ने विद्यार्थियों के घरों में जाकर बच्चों का मार्गदर्शन करने की कोशिश भी की लेकिन कोरोना के खतरों के कारण आगे बढ़े कदम फिर से ठिठक गए। ऑनलाइन शिक्षा ने भले ही समाज के साधन-सम्पन्न व जागरूक वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षति कम की हो लेकिन समाज के वंचित वर्ग के बच्चों पर ऑनलाइन शिक्षा भारी पड़ी है। राइट टू एजुकेशन फोरम ने सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज और चैंपियंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के साथ मिलकर देश के 5 राज्यों में जो अध्ययन किया है, उसके नतीजे डरावने हैं। 'मैपिंग द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19' नाम से हुए अध्ययन के मुताबिक लड़कियों की शिक्षा पर सबसे अधिक बुरा असर हुआ है। भारत में माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रही दो करोड़ लड़कियां स्कूल ही नहीं लौट पाएंगी। अध्ययन में यूनिसेफ के एजुकेशन प्रमुख टेरी डर्नियन के अलावा बिहार स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अध्यक्ष प्रमिला कुमारी ने इस मुद्दे पर गहरी चिंताएं व्यक्त की हैं। जून महीने में 3176 परिवारों पर हुए सर्वे में उत्तर प्रदेश के 11, बिहार के 8, असम के 5, तेलंगाना के चार व दिल्ली के एक जिले को शामिल किया गया। अध्ययन में आर्थिक-सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों से बातचीत के दौरान लगभग 70 फीसदी लोगों ने माना कि उनके पास खाने को भी पर्याप्त राशन नहीं है। ऐसे हालात में पढ़ाई और उसमें भी लड़कियों की पढ़ाई सबसे ज्यादा खतरे में है। अध्ययन में सामने आया है कि किशोरावस्था की लगभग 37 फीसदी लड़कियां अपने स्कूल लौटने को लेकर आशंकित व डरी हुई हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि पितृ सत्तात्मक समाज में लड़कियों के साथ विभिन्न प्रकार से भेदभाव किया जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों से जल्दी स्कूल छुड़वा लिया जाता है। हालांकि शिक्षा का अधिकार कानून ने छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है लेकिन लैंगिक भेदभाव के कारण बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। संकटों व महामारियों में लैंगिक भेदभाव और अधिक प्रचंड हो जाता है। कोरोना के संकट में शिक्षा पूरी तरह डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हो गई है। स्मार्ट फोन व इंटरनेट की सुविधा होने पर भी घर में यदि पढ़ने वाले बच्चे लड़के और लड़कियां हैं तो लड़कों की पढ़ाई को प्राथमिकता मिलती है। इस तरह से लड़कियों के लिए यह सत्र बेकार जा रहा है। अध्ययन में केवल 26 फीसदी लड़कियों ने माना कि उन्हें पढ़ाई के लिए फोन मिल पाता है। अध्ययन में यह बात भी देखी गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की अपेक्षा निजी स्कूलों के बच्चे इस बात पर पक्का थे कि कोरोना खत्म होने पर स्कूल लौट पाएंगे। कोरोना ने बच्चों को घर पर ही रहने को मजबूर कर दिया है। ऑनलाइन शिक्षा में प्रायः देखने में आता है कि लड़के तो स्मार्ट फोन देकर पढ़ने को बिठा दिए जाते हैं और लड़कियों को घर के कामों में लगा दिया जाता है। तकरीबन 71 प्रतिशत लड़कियों ने माना कि कोरोना के बाद से वे केवल घर पर हैं और पढ़ाई के समय में भी घरेलू काम करती हैं। वहीं लड़कियों की तुलना में केवल 38 प्रतिशत लड़कों ने बताया कि उन्हें घरेलू काम करने को कहे जाते हैं। लड़कियों की पढ़ाई रुकने की स्थिति में बाल विवाह का भी खतरा मंडराने लगता है। कम उम्र में उन्हें गृहस्थी की गाड़ी में झोंक दिया जाता है। इससे उनका पढ़ाई से पूरी तरह नाता टूट जाता है। शिक्षा के फैलाव ने स्थितियों में जो सुधार किया था, कोरोना के कारण यथास्थिति का खतरा पैदा हो गया है। समाज के वंचित वर्ग के बच्चों विशेष तौर पर लड़कियों की शिक्षा पर कोरोना के दौरान और बाद में स्कूल खुलने पर लड़कियों की उपस्थिति और पढ़ाई पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए स्कूलों को तो काम करना ही होगा, बल्कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

आज का राशिफल

मेष व्यावसायिक व पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जारी प्रयास सार्थक होंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शासन सत्ता से तनाव मिलेगा। गृह सुख में कमी रहेगी।

वृषभ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक योजनायें सफल होंगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मिथुन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। उदर विकार या नेत्र विकार की संभावना है। पारिवारिक जनों से पीड़ा मिलने के योग हैं। वाणी की सौम्यता व्यर्थ के विवादों से आपको बचा सकती है।

कर्क पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खान-पान में संयम रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

सिंह पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। धन लाभ की संभावना है।

कन्या पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। मांगलिक कार्यो में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

तुला जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

वृश्चिक परिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

धनु पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा।

मकर आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वाद विवाद की स्थिति आपके हित में न होगी।

कुम्भ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। भारी व्यय का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मीन व्यावसायिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। वाणी की असभ्यता आपको किसी संकट में डाल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शासन सत्ता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

PM स्वनिधि योजना के तहत 36,000 रेहड़ी-पटरी वालों को जोड़ेगी swiggy

नेशनल न्यूज। ऑनलाइन खाना मंगाने के मंच स्विगी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (**PM** स्वनिधि) योजना के तहत वह रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अपनी योजना का विस्तार 125 शहरों में करेगी। स्विगी ने एक बयान में कहा कि पहले चरण के तहत कंपनी 36,000 रेहड़ी-पटरी वालों को जोड़ेगी, जिसके तहत 125 शहरों में उसके मंच के जरिए ऋण दिया गया है। इसके लिए स्विगी ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ अहमदाबाद, वाराणसी, चेन्नई, दिल्ली और इंदौर में एक पायलट परियोजना लागू की थी, जिसके तहत 300 से अधिक रेहड़ी-पटरी वाले पहले ही उसके मंच से जुड़ गए हैं। कंपनी ने बयान में कहा कि उसके मंच से जुड़ते समय रेहड़ी-पटरी वालों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (**FSSAI**) के साथ पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। स्विगी के **COO** विवेक सुंदर ने कहा कि सुरक्षा और सफाई के साथ उपभोक्ताओं के दरवाजे तक विविधतापूर्ण भोजन पहुंचाने वाले मंच के रूप में हमें उन पसंदीदा स्ट्रीट फूड को लाने की खुशी है, जो कई महीनों से नदारद थे। उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी से खानपान भारत में आम जिंदगी का हिस्सा है और स्वीगी आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय को धन्यवाद देती है कि उन्होंने स्विगी को यह मौका दिया।

इक्विटी म्यूचुअल फंड से नवंबर में 12,917 करोड़ रुपये की निकासी

नई दिल्ली। इक्विटी म्यूचुअल फंड से नवंबर में 12,917.36 करोड़ रुपये की निकासी (नेट आउटफ्लो) हुई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। आसान शब्दों में कहा जाए तो म्यूचुअल फंड के इक्विटी सेगमेंट से निवेशकों ने नवंबर में कुल 12,917.36 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। सितंबर महीने में इक्विटी स्कीम से 734.40 करोड़ रुपये, जबकि अक्टूबर में 2,724.95 करोड़ रुपये निकाले गए थे। इसके अलावा जुलाई में आउटफ्लो 2,480.35 करोड़ रुपये जबकि अगस्त में आउट फ्लो 4,000 करोड़ रुपये रहा।

भारत की क्षमता बड़े पैमाने पर है: पीएलसी के वैश्विक सीईओ

ब्रिटिश एफएमसीजी प्रमुख आरबी पीएलसी के वैश्विक सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन ने बुधवार को कहा कि भारतीय बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं और यह भविष्य के कई नवाचारों का स्रोत हो सकता है। उन्होंने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि इनोवेशन से उपभोग वर्ग की क्षमता बढ़ेगी। नरसिम्हन ने अपने आभासी संबोधन में कहा, ÷मैं इस बात को लेकर बहुत आशान्वित हूं कि भविष्य में भारत से बहुत कुछ नवाचार होगा। मेरी नजरें इसके लिए हैं। **RB** भारत में डेटॉल, लिज़ोल और हार्पिक सहित कई स्वच्छता उत्पादों की बिक्री करता है, जबकि स्वास्थ्य खंड में इसके कुछ लोकप्रिय ब्रांड जैसे डिस्प्रिन और स्ट्रेप्सिल्स हैं। नरसिम्हन ने यह भी कहा कि महामारी के बाद की दुनिया में उपभोक्ता व्यवहार का अधिक स्थायी समाधान दिखाई देगा, और जो बदलाव डिजिटल की ओर हुआ है वह रहने वाला है। नरसिम्हन ने यह भी कहा कि महामारी के बाद की दुनिया में उपभोक्ता व्यवहार का अधिक स्थायी समाधान दिखाई देगा, और जो बदलाव डिजिटल की ओर हुआ है वह रहने वाला है। महामारी चरण ने ÷उपभोक्ता के अनुभवों को फिर से परिभाषित करने÷ और ÷जागरूक उपभोग÷ के लिए प्रेरित किया है।

वित्त मंत्री ने की MSMEs की बकाया राशि के भुगतान की समीक्षा, जानें पूरा ब्योरा

नई दिल्ली।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने **CPSEs** और केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (**MSMEs**) की बकाया राशि से जुड़ी स्थिति की गुरुवार को समीक्षा की। वित्त सेवा विभाग में सचिव देवाशीष पांडा, **MSME** सचिव ए के शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस साल मई में घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्रीय एजेंसियों और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (**CPSEs**) के पास अगर **MSMEs** कंपनियों का किसी तरह का बकाया था, तो उसका भुगतान 45 दिन के भीतर किया जाना था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, मई 2020 से भारत सरकार और **MSME** मंत्रालय ने बकाया राशि के भुगतान के लिए नियमित फॉलो-अप और ठोस प्रयास किए हैं। **MSMEs** को बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्रीय लोक उपक्रमों और केंद्र सरकार की एजेंसियों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार की एजेंसियों और **CPSEs** ने पिछले सात महीने में **MSMEs** को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है। **MSME** मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अक्टूबर में सबसे ज्यादा 5,100 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई और 4,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। नवंबर के पहले 10 दिन में 4,700 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई और करीब 4,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। बयान के मुताबिक इस तरह नवंबर में अक्टूबर के मुताबिक इस मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।

इस बयान में कहा गया है कि **MSME** विभाग के सचिव ने इस संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रियों एवं **CPSEs** को कई बार पत्र लिखा और निजी स्तर पर बातचीत भी की। इसके अलावा **PMO** और कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी इसको लेकर प्रयास किया।

महामारी के दौरान केन्या में एटीएम की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट

नैरोबी. कोविड-19 महामारी ने केन्या में डिजिटल वित्तीय लेनदेन को तेज कर दिया है, जो कि स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) के लिए एक झटका है। यहां एटीएम के कारोबार में पिछले आठ महीनों में तेजी से गिरावट आई है। ये बात यहां के सेंट्रल बैंक के एक नए आंकड़े से पता चली है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि अक्टूबर के अंत में इस पूर्वी अफ्रीकी देश में 2,409 एटीएम थे, जबकि जनवरी में 2,459 थे। यह लगभग 10 महीनों में 50 मशीनों की गिरावट है। सबसे ज्यादा गिरावट दूसरी और तीसरी तिमाही में दर्ज की गई। अब ये कुल संख्या के सात साल के निचले स्तर तक पहुंच गई। एटीएम की संख्या गिरने से महामारी के दौरान मोबाइल मनी का उपयोग केन्या में 528.9 बिलियन शिलिंग (लगभग 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है।

फ्रांस ने गूगल पर लगाया 120 मिलियन डॉलर का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

बिजनेस डेस्क: फ्रांस के डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर (**CNIL**) ने गूगल और ऐमजॉन पर बड़ा जुर्माना लगाया है। रेगुलेटर ने गूगल पर ऑनलाइन ऐडवर्टाइजिंग ट्रैकर्स (कुकीज) से जुड़े फ्रांस के नियमों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया है। गूगपर पर 120 मिलियन डॉलर (करीब 892 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया है। रेगुलेटर की ओर से गूगल पर लगाया गया यह सबसे बड़ा जुर्माना है। डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर **CNIL** ने कहा है कि अमेरिका की ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी ऐमजॉन (**Amazon**) पर इन्हीं नियमों का उल्लंघन करने पर 35 मिलियन यूरो (3.5 करोड़ यूरो) का जुर्माना लगाया गया है। रेगुलेटर ने पाया है कि गूगल और ऐमजॉन की फ्रेंच वेबसाइट्स ने कंप्यूटर्स पर ऐडवर्टाइजिंग कुकीज सेव (**Save**) करने से पहले विजिटर्स की पूर्व अनुमति नहीं ली। फ्रेंच रेगुलेटर **CNIL** ने कहा है कि गूगल और ऐमजॉन इंटरनेट यूजर्स को यह स्पष्ट जानकारी देने में भी नाकाम रहे कि दोनों फर्में ऐसे ऑनलाइन ट्रैकर्स का किस तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं और उनकी फ्रेंच वेबसाइट्स के विजिटर्स, कुकीज के इस्तेमाल को कैसे इनकार कर सकते हैं। **CNIL** ने कहा है कि गूगल और ऐमजॉन के पास इंफॉर्मेशन बैनर्स बदलने के लिए 3 महीने का वक्त है। अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें मोडिफिकेशंस किए जाने तक हर दिन 1 लाख यूरो का अतिरिक्त फाइन देना होगा

सैमसंग ने लॉन्च किया नया 110 इंच का माइक्रो एलईडी टीवी

सोल.

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुरुवार को एक नया माइक्रो एलईडी टीवी लॉन्च किया है। इसके जरिए दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज अपने उपभोक्ताओं को घर पर मनोरंजन का एक बेहतर अनुभव देना चाहता है। सैमसंग की 110 इंच की माइक्रो एलईडी टीवी की कीमत 1,56,400 डॉलर होगी। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, नई लक्जरी टीवी के लिए प्री-ऑर्डर इस महीने के आखिर से शुरू होंगे और 2021 की पहली तिमाही में इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग होगी। सैमसंग ने कहा कि उसका लक्ष्य इस टीवी को संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों में बेचने का है, लेकिन बाद में वह इसकी वैश्विक उपलब्धता का विस्तार करेगा।

सैमसंग के विजुअल डिस्प्ले बिजनेस के एक्जिक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट चू जोंग-सुक ने एक ऑनलाइन इवेंट में कहा, सैमसंग ने माइक्रो एलईडी टीवी बाजार को बनाने और उसका नेतृत्व करने का लक्ष्य रखा है। हमें विश्वास है कि हम इस प्रोडक्ट को बड़ी संख्या में बेचेंगे।

माइक्रो एलईडी टीवी माइक्रोमीटर के आकार के एलईडी चिप्स को सिंग्युलर पिक्सेल के रूप में उपयोग करता है जो कि बेहतर रिजॉल्यूशन और हायर क्लियरिटी देता है। सैमसंग ने पहली बार अपने वॉल एलईडी डिस्प्ले को 2018 में द वॉल नाम के ब्रांड के तहत कमर्शियल उपयोग के लिए लॉन्च किया था, लेकिन यह होम सिनेमा के लिए भी प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहा है।

सैमसंग ने कहा कि वह भविष्य में 70 इंच से लेकर 100 इंच तक के स्क्रीन साइज वाले माइक्रो एलईडी टीवी लाने के विकल्प देख रहा है। उसका नया 110 इंच माइक्रो एलईडी टीवी 3.3-वर्ग मीटर क्षेत्र में 8 मिलियन से अधिक आरजीबी एलईडी चिप्स का उपयोग करता है, जो 4के रिजॉल्यूशन की क्वालिटी देता है। इसमें एक माइक्रो एआई प्रोसेसर भी है। सैमसंग ने कहा कि वह नए माइक्रो एलईडी टीवी को हाई-एंड यूजर्स में बढ़ावा देने के लिए खासी मार्केटिंग करेगा। चू ने कहा, ÷हम इसे सामान्य एलसीडी टीवी की तरह नहीं बेचने जा रहे हैं। इसकी महंगी कीमत के बारे में पूछे जाने पर सैमसंग ने कहा कि यदि माइक्रो एलईडी टीवी मार्केट में आते हैं तो नाटकीय रूप से इसकी कीमतें कम हो जाएंगी।

फेसबुक का पलटवार, कहा-अमेरिकी मुकदमा 'इतिहास में बदलाव' चाहता है

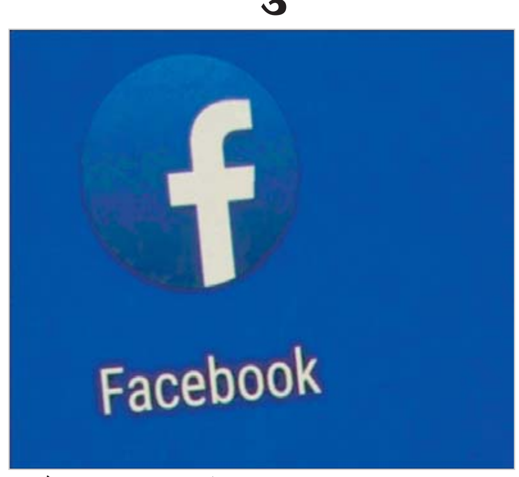

सैन फ्रांसिस्को . जैसे ही अमेरिकी सरकार ने फेसबुक को तोड़ने की अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए मुकदमा किया, तुरंत ही सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने यह कहते हुए पलटवार किया कि यह केवल इतिहास को नए तरीके से इंटरपेट्र करना नहीं है, बलिक्य ये भी देखना है कि यह कानून कैसे काम करे। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसिल जेनिफर न्यूस्टेड ने बुधवार की देर रात कहा कि कंपनी अदालत में अपने दिन का इंतजार कर रही है, ÷जब हम विश्वास के साथ यह सबूत दिखाएंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक साथ हैं और वह अपनी योग्यता के आधार पर महान उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।÷

अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) और राज्य के अटॉर्नी जनरल ने फेसबुक के उन 2 अधिग्रहणों पर हमला किया है जो फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को और 2014 में व्हाट्सएप को अधिग्रहीत करके किए थे। फेसबुक के अनुसार, इन दोनों अधिग्रहणों की समीक्षा उस समय के प्रासंगिक एंटीट्रस्ट रेगुलेटर्स ने की थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा, ÷कई साल बीत चुके हैं। उन सुलझे हुए कानून या नवाचार और निवेश के परिणामों के बारे में कोई सम्मान नहीं है। अब एजेंसी कह रही है कि यह गलत है और वह इसमें संशोधन चाहती है। यह इतिहास में बदलाव करने के अलावा और कुछ नहीं है।÷ द्विदलीय समर्थन द्वारा सुर्खियों में आने वाली एक ऐतिहासिक कार्रवाई में अमेरिका की संघीय सरकार और 48 राज्यों ने फेसबुक पर लैंडमार्क एंटीट्रस्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया है। इसमें फेसबुक पर बाजार की प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के स्पिनऑफ के लिए जोर दे रहा है, यानि कि वह इन दो सब्सिडियरी कंपनियों का बिजनेस पैरेंट कंपनी से अलग करने के लिए कह रहा है।

फेसबुक ने कहा, ÷जब हमने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया, तो हमें विश्वास था कि ये कंपनियां हमारे फेसबुक उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत लाभकारी होंगी और हम उन्हें कुछ बेहतर तरीके से बदलाव करने में मदद कर सकते हैं और हमने ऐसा किया। यह मुकदमा अमेरिकी सरकार की अपनी विलय समीक्षा प्रक्रिया के बारे में संदेह और अनिश्चितता का जोखिम लाता है कि क्या अधिग्रहण करने वाले बिजनेस वास्तव में कानूनी प्रक्रिया के परिणामों पर भरोसा कर सकते हैं।÷

बता दें कि फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को 1 बिलियन डॉलर और 2014 में व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर में खरीदा था। जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा था, तब उसके पास आज के कुल उपयोगकर्ताओं के लगभग 2 प्रतिशत उपयोगकर्ता ही थे और सिर्फ 13 कर्मचारी थे। ना कोई राजस्व था और ना कोई वास्तविक बुनियादी ढांचा था।

आज इंस्टाग्राम के एक अरब से ज्यादा मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। पूरे विश्व में व्हाट्सएप के दो अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं, भारत में ही 40 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। कंपनी ने कानूनी लड़ाई के लिए तैयार होने की बात कहते हुए कहा, ÷इंस्टाग्राम को फेसबुक का हिस्सा बनाने से उपभोक्ताओं और व्यवसायों को जबरदस्त लाभ हुआ है। इंस्टाग्राम अधिक विश्वसनीय हो गया और उन तकलीफों से बच गया, जिसके कारण अन्य तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पटरी से उतर गए। इसी तरह व्हाट्सएप को भी फेसबुक का हिस्से बनाने से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। हमने दुनिया भर के उपभोक्ताओं को एसएमएस के बदले एक मुफ्त मैसेजिंग विकल्प की पेशकश की थी और मोबाइल ऑपरेटर इसके लिए शुल्क ले रहे थे।÷

लॉकडाउन में बची छुट्टियां अब नहीं होगी बर्बाद, कंपनियों ने स्टाफके लिए बदले नियम

नेशनल डेस्क:

उतार चढ़ाव से भरे वर्ष 2020 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस साल देश पर आए कोरोना संकट के चलते लोग कई महीनों तक घरों में ही कैद रहने को मजबूर हुए। लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, जिससे नौकरीपेशा लोगों को घर से ही काम करने का मौका मिला। ऐसे में समय की बचत के साथ साथ कर्मचारियों की छुट्टियों में भी काफी बचत हुई। अब इन्ही बची हुई छुट्टियों को लेकर कुछ कंपनियों ने नए बदलाव किए हैं।

कर्मचारियों को कैश का करेंगे भुगतान

परंपरागत सोच से हटकर नई पहल करने वाली कंपनियों में आरपीजी ग्रुप, माइंडट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा और कैशकरो सहित कई कंपनियों के नाम जुड़ गए हैं। जहां कुछ कंपनियां बची हुई छुट्टियों के लिए कर्मचारियों को कैश का भुगतान कर रही हैं तो वहीं अन्य अपने स्टाफको अगली तिमाही (जनवरी-मार्च) तक अपनी बची हुई छुट्टियां का इस्तेमाल करने का इजाजत दे रही है।

यह साल दूसरे सालों के मुकाबले अलग

अब तक की व्यवस्था के मुताबिक अगर आप छुट्टियां नहीं लेते थे तो वे साल खत्म होने के साथ ही बेकार चली जाती थीं लेकिन इस बार कंपनियों ने परंपरागत सोच को बदल डाला है। आरपीजी ग्रुप के चीफ टैलेंट ऑफिसर सुप्रतीक भट्टाचार्य ने इसकी विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह साल दूसरे सालों के मुकाबले अलग है। हमने फैसला किया है कि हमारे कर्मचारी इस साल की बची हुई छुट्टियों को अगले साल की दूसरी तिमाही तक इस्तेमाल कर सकते हैं

बोइंग 737 मैक्स विमान का परिचालन ब्राजील में फिर से शुरू

ब्रासीलिया।

बोइंग 737 मैक्स विमान ने ब्राजील में उड़ान का संचालन फिर से शुरू कर दिया है. दो घातक दुर्घटनाओं के बाद इसका पूरी दुनिया में परिचालन रोक दिया गया था. एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को विमान ने साओ पाउलो और पोटरे एलेग्रे के बीच पहली उड़ान भरी. हालांकि एयरलाइन ने इस उड़ान के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया. मार्च 2019 में भारत सरकार ने अगली सूचना तक बोइंग 737 मैक्स के 8 मॉडल विमानों के परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की थी. लायन एयर फ्लाइट 610 (अक्टूबर 2018) और इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 (मार्च 2019) के क्रैश के बाद मैक्स का 2019 मार्च से वैश्विक स्तर पर परिचालन बंद था. इन दुर्घटनाओं में कुल 346 लोगों की जान गई थी. जांच में पता चला कि विमान के प्रमुख उड़ान नियंत्रण सॉफ्टवेयर में खराबी होने के चलते दो घातक दुर्घटनाएं हुई. 2 दिसंबर को अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा संचालित एक बोइंग 737 मैक्स विमान ने डलास से टेक्सस, तुलसा और ओक्लाहोमा के लिए अपना पहला वाणिज्यिक परिचालन किया था.

वैक्सीन के खर्च आकलन में जुटा वित्त मंत्रालय, बजट में हो सकता है प्रावधान

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन के जल्द ही बाजार में आने की सुगबुगाहट को देखते हुए वित्त मंत्रालय इन दिनों वैक्सीन पर होने वाले सरकारी खर्च के आकलन में जुट गया है। टीकाकरण पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए मंत्रालय अगले वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इस खर्च का प्रावधान कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन खर्च को लेकर वित्त मंत्रालय के सचिवों के बीच कई बैठकें भी हो चुकी हैं। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण बढ़ रहे राजकोषीय घाटे के बावजूद वित्त मंत्रालय वैक्सीन पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बात के संकेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पहले भी दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक खर्च को पूरा करने के और भी कई ऐसे उपायों को तलाशा जा रहा है जिससे सरकार के खजाने पर कम से कम दबाव पड़े। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले कुछ सप्ताह में वैक्सीन आने की बात कही थी। वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र की तीन अग्रणी कंपनियां फाइजर, भारत बायोटेक व एस्ट्राजेनेका ने भारत सरकार से टीकाकरण की अनुमति मांगी है जिस पर जल्द ही फैसला किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अभी भारत में वैक्सीन की खरीदारी, उसके स्टोरेज व टीकाकरण पर होने वाले खर्च को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से इन सभी कार्यो पर होने वाले खर्च का मोटा अनुमान लगाया जा रहा है और उसके आधार पर एक बजटीय प्रावधान तैयार किया जा सकता है। इस साल स्वास्थ्य के मद में होने वाले बजटीय प्रावधान को भी दोगुना किया जा सकता है। ताकि टीकाकरण का काम किसी भी हाल में प्रभावित नहीं हो। सूत्रों के मुताबिक टीकाकरण की एक बार शुरुआत के बाद यह काम एक साल से अधिक समय तक चल सकता है, इसलिए वित्तीय व्यवस्था भी पूरे साल के लिए की जाएगी। मोटे अनुमान के मुताबिक 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन की जरूरत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीकाकरण की पूरी चेन पर होने वाले खर्च में राज्य सरकार व निजी कंपनियों की भी भूमिका होगी, लेकिन वैक्सीन पर होने वाले खर्च का रोडमैप केंद्र सरकार ही तैयार करेगी जिसमें वित्त मंत्रालय की अहम भूमिका होगी। यह भी संभव है कि राज्यों को टीकाकरण के लिए सरकार की तरफ से अलग से अनुदान दिए जाए जिसकी घोषणा बजट में हो सकती है।

सरकार बिक्री पेशकश के जरिये IRCTC में बेचेगी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी, 1,367 रुपये न्यूनतम दाम तय

नई दिल्ली।

सरकार की रेलवे उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टुरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) में बाजार में खुली पेशकश (ओएफएस) के जरिये 20 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने की योजना है। यह पेशकश गुरुवार को खुल सकती है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचित तुहीन कांत पांडे ने एक ट्वीट में कहा, गैर-खुदरा निवेशकों के लिये आरआरसीटीसी में बिक्री पेशकश कल खुल रही है। दूसरे दिन यह खुदरा निवेशकों के लिये होगी। सरकार इसमें पांच प्रतिशत ग्रीन शू विकल्प के साथ 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। बिक्री पेशकश के लिये 1,367 रुपये का न्यूनतम मूल्य रखा गया है। इस खबर के बाद शुरुआती कारोबार में आईआरसीटीसी के शेयर आज 10त्न से नीचे आ गए। आईआरसीटीसी का शेयर बुधवार को कारोबार की समाप्ति पर 1,618.05 रुपये पर बंद हुआ। यह पिछले दिने के बंद भाव के मुकाबले 1.55 प्रतिशत नीचे रहा। कंपनी की प्रवर्तक भारत सरकार इस बिक्री पेशकश के तहत कुल अपने 3.2 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी जिससे उसे 4,374 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

कोविड- 19 के कारण सरकार के खजाने पर काफी दबाव है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से आने हैं जबकि 90 हजार करोड़ रुपये की राशि वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचने से प्राप्त होंगे। सरकार की आईआरसीटीसी में वर्तमान में 87.40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सेबी के दिशानिर्देशों के तहत सरकार को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 प्रतिशत पर लानी है। बता दें कि रेल यात्रियों को ट्रेन टिकट बुक करवाते समय अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल के रूप में स्वयं का मोबाइल नंबर ही रजिस्टर करवाना होगा। भारतीय रेलवे द्वारा रविवार को यह घोषणा की गई थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि कुछ रेल यात्री अपने ट्रेन टिकट एजेंट या दूसरों के आईआरसीटीसी (**IRCTC**) अकाउंट्स से खरीदते हैं। ऐसे में यात्री का स्वयं का कॉन्टैक्ट नंबर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (**PRS**) में रजिस्टर नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर ट्रेन कैंसिल होती है या ट्रेन के समय में बदलाव होता है, तो यात्रियों के मोबाइल नंबर पर सूचना नहीं पहुंच पाती है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

विराट कोहली आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर

दुबई। (एजेंसी)।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में 3 मैचों की श्रृंखला में 2 अर्द्धशतक जमाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी एक दिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। कोहली ने दूसरे और तीसरे वनडे में 89 और 63 रन बना। उनके रैंकिंग में 870 अंक हैं।

हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वनडे श्रृंखला से बाहर रोहित शर्मा (842) दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम उनसे पांच अंक पीछे तीसरे स्थान पर हैं। विश्व कप 2019 के बाद पहला वनडे खेलने वाले हरफनमौला हार्दिक पांड्या ने पहले मैच में 90 और तीसरे में नाबाद 92 रन बनाए थे। वह पहली बार 553 अंक लेकर शीर्ष 50 बल्लेबाजों में 49वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

ऑस्ट्रेलियाई टीम में से कप्तान आरोन फिंच कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 791 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पहले दो मैचों में शतक जमाने वाले स्टीव स्मिथ 2018 के बाद पहली बार शीर्ष 20 में आकर 15वें स्थान पर हैं। ग्लेन मैक्सवेल फरवरी 2017 के बाद पहली बार शीर्ष 20 में पहुंचे हैं और 20वें स्थान पर हैं। गेंदबाजों में भारत के जसप्रीत बुमराह 700 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंडके ट्रेंट बोल्ट 722 अंक लेकर शीर्ष पर और अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान दूसरे स्थान पर हैं। एडम जम्पा पहली बार 14वें स्थान पर पहुंचे हैं।

कोहली एकदिवसीय में इस दशक के सबसे प्रभावशाली भारतीय खिलाड़ी : गावस्कर

मुंबई। (एजेंसी)

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि मैच जिताऊ प्रदर्शन के मामले में कप्तान विराट कोहली पिछले 10 वर्षों में भारत के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी रहे हैं। भारत के लिए 2008 में पदार्पण करने वाले कोहली पिछले एक दशक में सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन कर उभरे है। उन्होंने हाल में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकार को पीछे छोड़ते हुए एकदिवसीय में सबसे तेजी से 12,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। गावस्कर ने 'स्टार स्पोर्ट्स' के कार्यक्रम 'क्रिकेट कनेक्टेड' में कहा, 'मुझे लगता है कि अगर आप व्यक्तिगत प्रदर्शन को देखते है तो निश्चित रूप से वह विराट कोहली होंगे। रनों का पीछा करते हुए उनके प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने बहुत सारे मैच जीते है।' गावस्कर ने कहा, 'मैं सिर्फ रन और विकटों की संख्या की जगह खिलाड़ी के प्रभाव को देखता हूं और इस मामले में आपको मानना होगा कि यह दशक विराट कोहली का है। भारतीय टीम के द्वारा जीते गए मैचों पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है।'गावस्कर के विचार से हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन इत्तेफाक नहीं रखते, जिनका मानना है कि महेन्द्र सिंह धोनी इस दशक के सबसे अधिक प्रभाव वाले भारतीय खिलाड़ी है। धोनी ने इस साल अगस्त में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। हेडन ने कहा, 'यह काफी महत्वपूर्ण और अहम है कि धोनी ने विश्व कप और चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता। मेरे लिए विश्व कप का खिताब मील के पत्थर की तरह है।'

10 साल की वैष्णवी तिवारी ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर किया योगाभ्यास, इन दो रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

अक्टूबर महीने के आखिरी दिनों में जहाँ दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिरकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं आयकर कॉलोनी, पीतमपुरा में रहने वाली वैष्णवी तिवारी ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बुढा मध्यमहेश्वर, चंद्रशिला चोटी एवं तुंगनाथ, उत्तराखंड में योगाभ्यास करके इंडिया बुक ऑफ़ रिकाड्र्स एवं एशिया बुक ऑफ़ रिकाड्र्स में अपना नाम दर्ज कराया है।

जी हाँ, बात करतें हैं आयकर कॉलोनी, पीतमपुरा, दिल्ली में रहने वाले नील कमल तिवारी की 10 वर्षीय पुत्री वैष्णवी तिवारी का जो एस डी पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा में पांचवी क्लास की छात्रा है एवं योगगुरु हेमंत शर्मा के निर्देशन में योगाभ्यास करती है. वैष्णवी ने 30 अक्टूबर, 2020 को अपने पंचकेदार दर्शन के दौरान बुढा मध्यमहेश्वर में 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया इसके लिए वैष्णवी तिवारी का नाम इंडिया बुक ऑफ़ रिकाड्र्स एवं एशिया बुक ऑफ़ रिकाड्र्स में 'सबसे कम उम्र में 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग करने का रिकॉर्ड' के रूप में दर्ज हुआ है. इसके साथ ही चंद्रशिला छोटी पर जो की 13,000 फीट की ऊंचाई पर है एवं तुंगनाथ मंदिर प्रांगन में जो की 12,070 फीट की ऊंचाई पर है में भी इन्होने योगाभ्यास किया।

एक तरफ इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद लोगो को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, साँस लेने में कठिनाई होती है एवं हाई अल्तिच्युड सिकनेस के शिकार हो जाते है, ऐसे में काफी कम तापमान में इस ऊंचाई पर एक 10 साल के बच्चे द्वारा योग करना वाकई एक तारीफ भरा काम है वैष्णवी का कहना है की यह सब योग से ही संभव हो सका है. वह रोजाना एक घंटे योग करती है जिससे उसे ऐसा फिटनेस मिला है. वह अपने पापा से प्रेरणा लेती है जो प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठाकर योग करते है, मैराथन भागते है एवं पहाड़ो में ट्रैकिंग करते है. वैष्णवी का सपना है वह एक दिन बड़ा होकर माउन्ट एवेरेस्ट पर चढ़ेगी।

कप्तानी पर बोले स्टीव स्मिथ, टीम के लिये जो सही हो वह करने को तैयार

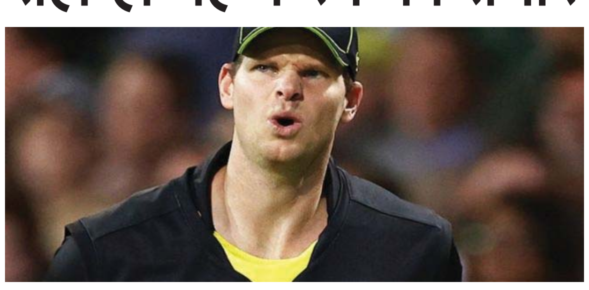

एडीलेड। (एजेंसी)।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने गुरूवार को कहा कि उनके दोबारा कप्तान बनने पर टीम में बात हो रही है और वह टीम के हित में कुछ भी करने के लिये तैयार हैं। स्मिथ और उपकप्तान डेविड वॉर्नर ने मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में गेंद से छेड़खानी मामले में भूमिका को लेकर पद छोड़ दिये थे। उसके बाद से टिम पेन टेस्ट टीम के और आरोन फिंच सीमित ओवरों में कप्तान हैं। स्मिथ ने आनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में दोबारा कप्तानी के सवाल पर कहा ,'' इस तरह की बातचीत हो रही है। कोच जस्टिन लैंगर ने इस बारे में जवाब दिया है।इसके लिये एक प्रक्रिया होती है जिसे पूरा करना होता है।'' छत्तीस वर्ष के पेन अपने कैरियर के आखिरी दौर में हैं लिहाजा नये कप्तान को लेकर बात हो रही है।

स्मिथ ने कहा कि वह टीम के हित में कुछ भी करने के लिये तैयार हैं। उन्होंने कहा ,'' मैं वही करूंगा जो टीम के हित में हो और टीम को आगे ले जाये। मेरे वश में जो कुछ होगा, मैं करूंगा।'' स्मिथ 2019 के बीच में प्रतिबंध की अवधि पूरी होने के बाद टीम में लौटे लेकिन कप्तानी नहीं की। उन्होंने कहा ,'' मैं अभी जहां हूं, उससे खुश हूं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, टीम के लिये जो सही होगा , वही करूंगा।'' आस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस को उपकप्तान बनाया है जबकि मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड को भविष्य के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है।

भारत ने टी20 श्रृंखला अपने नाम कर ली है। चोटिल फिंच की जगह मैथ्यू वेड ने कप्तानी की थी। कोच लैंगर ने कहा ,'' स्मिथ के दोबारा कप्तान बनने तक एक प्रक्रिया से गुजरना होगा।'' खिलाड़ियों की चोटों से परेशान आस्ट्रेलिया बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर सकता है। स्मिथ तीसरे नंबर पर उतर सकते हैं जबकि लाबुशेन पारी का आगाज कर सकते हैं। स्मिथ ने कहा ,'' इससे मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं। मैने तीसरे नंबर पर काफी बल्लेबाजी की है। तीसरे या चौथे या उससे नीचे भी आने से दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर कई बार पारी का पहला ओवर भी खेलना पड़ जाता है तो तीसरे नंबर पर उतरने वाला पारी का आगाज भी कर सकता है।

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच में विहारी और कुलदीप पर रहेंगी नजरें

सिडनी। (एजेंसी)

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले दूसरे अभ्यास मैच में भारत की नजरें दूसरे स्पिनर कुलदीप यादव या अतिरिक्त बल्लेबाज हनुमा विहारी पर रहेंगी चूंकि 17 दिसंबर से शुरू हो रहे दिन रात के पहले टेस्ट के लिये यह मैच 'ड्रेस रिहर्सल' की तरह होगा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाला दिन रात का यह मैच पहले टेस्ट की तैयारी के लिये अच्छा अवसर होगा। वैसे यहां की सपाट पिच एडीलेड ओवल की पिच से एकदम अलग है। इयान चैपल के अनुसार एडीलेड में पिच पर घास जमी होगी। इस मैच में विराट कोहली शायद नहीं खेलेंगे जिन्होंने संकेत दिया है किटेस्ट श्रृंखला के लिये वह अपनी तैयारी अलग से करेंगे। यह रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है ताकि आस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में उनकी तैयारी की भनक नहीं लग सके।

कोहली ने टी20 श्रृंखला खत्म होने के बाद कहा था ,'' मैं पूरा मैच खेलने में विश्वास रखता हूं। मैं फिजियो से बात करूंगा और अपनी तैयारी के बारे में फैसला लूंगा।''

आस्ट्रेलिया के नये उभरते खिलाड़ी कैमर ग्रीन के पास टीम प्रबंधन को प्रभावित करने का एक और मौका होगा। वहीं मिशेल स्वेपसन उम्मीद कर रहे होंगे कि अगले साल एससीजी पर होने वाले तीसरे टेस्ट में उन्हें मौका मिले। पहले अभ्यास मैच में भारत के लिये अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा पहली पारी में और रिधिमान साहा दूसरी पारी में अच्छा खेले लेकिन उनके अलावा बल्लेबाजों ने निराश ही किया। यह भारत के लिये टीम संयोजन तय करने का आखिरी मौका है। देखना यह है कि 36 टेस्ट खेल चुके केएल राहुल को तरजीह मिलती है या नहीं चूंकि मयंक अग्रवाल का सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलना तय है। अच्छी सीम और स्विंग गेंदबाजी के सामने पृथ्वी साव की कमजोर तकनीक की कलई खुल जाती है। वहीं शुभमन गिल शीर्ष स्तर पर खुद को स्थापित नहीं कर सकें हैं। ऐसे में कोहली और मुख्य कोच रवि शास्त्री अनुभव को प्राथमिकता दे सकते हैं।

अकरम के पीछे हटने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिल पा रहा मुख्य चयनकर्ता

नई दिल्ली। (एजेंसी)

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद अकरम ने चयन की मौजूदा व्यवस्था में काम करने से इनकार करते हुए नाम वापिस ले लिया है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया मुख्य चयनकर्ता नहीं मिल पा रहा। सूत्रों ने बताया कि अकरम इस पद के लिये पहली पसंद थे लेकिन उन्होंने शर्त रखी की चयन को लेकर पुरानी व्यवस्था लागू की जाये।

पुरानी व्यवस्था में बोर्ड मुख्य चयनकर्ता की अध्यक्षता में तीन या पांच सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति का गठन करता है जो टीमों को चुनती है और उस पर बोर्ड अध्यक्ष स्वीकृति जताते हैं।

नयी व्यवस्था अक्टूबर 2019 से लागू हुई जिसमें राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच मिसबाह उल हक थे जो मुख्य चयनकर्ता भी हैं । इसके अलावा समिति के बाकी सदस्य छह प्रांतीय टीमों के मुख्य कोच होते हैं। सूत्र ने कहा, 'अकरम ने कहा कि वह मौजूदा व्यवस्था में काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बोर्ड को उनकी सेवाएं लेनी है तो पुरानी व्यवस्था लागू करनी होगी। मिसबाह ने मुख्य चयनकर्ता के पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि मुख्य कोच के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने में उन्हें दिक्कत हो रही थी लिहाजा वह एक ही भूमिका निभाना चाहते हैं।'

चोटिल हेनरिक्स टीम इंडिया के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच से बाहर

सिडनी। (एजेंसी)।

हैमस्ट्रिंग खिंचाव से जूझ रहे ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला मोइजेस हेनरिक्स भारत के खिलाफ शुक्रवार को दूसरा दिन रात का अभ्यास मैच नहीं खेल सकेंगे। तैतीस वर्ष के हेनरिक्स को 12 सदस्यीय आस्ट्रेलिया ए टीम में चुना गया था हालांकि वह टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं।

'द वेस्ट आस्ट्रेलिया' की रिपोर्ट के अनुसार ,''हरफनमौला मोइजेस हेनरिक्स हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण गुलाबी गेंद से खेला जाने वाला दूसरा अभ्यास मैच नहीं खेल सकेंगे। आस्ट्रेलिया के चोटिल खिलाड़ियों की संख्या बढती जा रही है।''

क्वींसलैंड के हरफनमौला जैक विल्डरमथ को उनकी जगह आस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल किया गया है। इससे पहले डेविड वॉर्नर चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हैं।युवा बल्लेबाज विल पुकोवस्की को सिर में चोट लगी है जबकि जोश हेजलवुड और मिशेल स्टा र्क को भी मामूली चोटें हैं।

शाहबाज अहमद के दम पर तपन मेमोरियल ने जीता बंगाल टी20 चैलेंज का खिताब

कोलकाता। शाहबाज अहमद के आलराउंड खेल के दम पर तपन मेमोरियल ने बुधवार को यहां मोहन बागान को 33 रन से हराकर बंगाल टी20 चैलेंज का खिताब जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलने वाले शाहबाज ने चार छक्कों और दो चौकों की मदद से 41 गेंदों पर 54 रन बनाये जिससे तपन मेमोरियल ने छह विकेट पर 145 रन बनाये। शाहबाज ने इसके बाद दस रन देकर पांच विकेट लिये और मोहन बागान की टीम को 18 ओवर में 112 रन पर आउट करने में अहम भूमिका निभायी।

दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा डे-नाइट टेस्ट, भारत और इंग्लैंड के बीच होगा महामुकाबला

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

इंग्लैंड के खिलाफ दिन-रात्रि टेस्ट मैच की मेजबानी अहमदाबाद (गुजरात) का नव निर्मित मोटेरा स्टेडियम 24 फरवरी से करेगा , जहां चार मैचों की टेस्ट श्रृंखलाके एक अन्य मैच के अलावा पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाभी खेली जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को बताया कि फरवरी- मार्च (2021) में इंग्लैंड के भारतीय दौरे के लिए रोटेशन नीति के तहत टेस्ट श्रृंखला के दो अन्य मैचों की मेजबानी चेन्नई (पांच फरवरी से पहला टेस्ट मैच) को सौपी है जबकि तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला को पुणे (23 से 28 मार्च) में खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने गुरुवार को गुजरात क्रिकेट संघ के इंडोर अकादमी के उद्घाटन के दौरान मोटेरा को दिन-रात्रि टेस्ट की मेजबानी की घोषणा की।

पिछले साल ईडन गार्डन में बांग्लादेश के खिलाफ दिन-रात्रि टेस्ट के बाद गुलाबी गेंद से भारतीय सरजमीं पर यह दूसरा मुकाबला होगा। बीसीसीआई से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, '' चेन्नई श्रंखला के शुरुआती दो टेस्ट मैचों की मेजबानी करेगा जबकि अन्य दो मैच अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। '' विज्ञप्ति में कहा गया है, '' एक लाख 10 हजार दर्शकों की क्षमता वाला मोटेरा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियन है। दिन-रात्रि टेस्ट के बाद पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के मुकाबले भी अहमदाबाद में ही खेले जाएंगे। '' इंग्लैड़ के इस दौरे के आखिरी चरण में तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला होगी जिसके सभी मैच पुणे में खेले जाएंगे। बयान के मुताबिक, '' बीसीसीआई ने देश में मौजूदा स्थिति (कोविड-19) को देखते हुए इस दौरे के मैचों को तीन स्थलों तक सीमित रखने का फैसला किया है।'' शाह ने कहा, '' दोनों बोर्डों (बीसीसीआई और ईसीबी) ने विश्व क्रिकेट के दो ताकतवर टीमों के बीच प्रतिस्पर्धी मैचों वाली रोमांचक श्रृंखला के लिए मिलकर काम किया है।''

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरीसन ने कहा , '' बीसीसीआई ने तीन स्थानोंचेन्नई, अहमदाबाद और पुणे में जैव सुरक्षित माहौल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कराने की योजना बनाई है जिससे हमें खुशी है।'' उन्होने कहा, '' अहमदाबाद के शानदार सरदार पटेल स्टेडियम में खेलने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय टीम बनने की संभावना दौरे पर एक और आयाम जोड़ेगा।मुझे पता है कि यह ऐसा कुछ होगा जो खिलाड़ियों और प्रबंधन दोनों के लिए आकर्षक होगा।'' बीसीसीआई के एक सूत्र ने पुणे और चेन्नई को मेजबान चुनने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, '' हमारी रोटेशन

नीति के अनुसार, पुणे और चेन्नई को काफी समय पहले ही अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी करनी थी।इस श्रृंखला के साथ, उन्हें अपने लंबित मैचों की मेजबानी करने का मौका मिलेगा।'' उन्होंने कहा, '' बीसीसीआई की संचालन टीम ने बहुत विचार-विमर्श के बाद पाया कि ये तीनों स्थल इन दोनों टीमों के लिए बायो-बबल बनाने के लिएउपयुक्त हैं।'' यह समझा जा रहा है कि इंग्लैंड की सफल मेजबानी के बाद आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) का देश में आयोजन करने का दरवाजा खुल जाएगा। कोविड-19 के कारण आईपीएल के पिछले सत्र को यूएई में खेला गया था।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के विधेयक को मंजूरी दी

मुंबई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन के लिए मसौदा विधेयक को बुधवार को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य सरकार ने बजट में इस विश्वविद्यालय की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि इस विधेयक को अगले सप्ताह राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मसौदा मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विजय खोले की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

क्या अक्षय कुमार ने बंद कर दिया फ्रेशर एक्ट्रेस के साथ काम करना? दीपिका पादुकोण है इसका कारण

बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से कोई कुछ नया करने की सोच ही नहीं रहा है। पुरानी हिट फिल्मों का रीमेक बनाया जा रहा है या फिर साउथ इंडियन फिल्मों को कॉपी। इसके अलावा एक परंपरा और भी है फिल्में की सीरीज बनाने की। 5 साल से साजिद नाडियाडवाला हाउसफुल की सीरीज बना रहे हैं। फिल्म में एडल्ट कॉमेडी होती है और हंसने के नाम पर दर्शक सिनेमाहॉल तक खिचे चले आते हैं। इस फॉर्मूले को आधार बना कर हाउसफुल की कड़ियां बनाई जा रही हैं। इस बार एक रिपोर्ट के अनुसार हाउसफुल 5 के लिए साजिद नाडियाडवाला की टीम तैयार हो रही है। इस बार फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ कई बड़े सितारों को फिल्म में लेने की प्लानिंग हो रही हैं।

ताजा रिपोर्ट की मानें तो साजिद नाडियाडवाला जल्द ही हाउसफुल 5 का ऐलान कर सकते हैं। फिल्म को लेकर जो जानकारी सामने आ रही हैं कि इस बार फिल्म में किसी फ्रेशर एक्ट्रेस या नये चेहरे को नहीं लिया जाएगा। इस बार अक्षय कुमार की जोड़ी दीपिका पादुकोण के साथ नजर आयेगी। यानी की पहली बार दर्शक अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण को साथ में स्क्रीन पर देखेंगे। इस बार हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार के साथ दीपिका पादुकोण, कृति सैनन, अभिषेक बच्चन जैकलीन फर्नांडिस, जॉन अब्राहम और पिछली फिल्मों के कुछ स्टार्स नजर आएंगे।

अक्षय कुमार पिछले कुछ सालों से अपनी फिल्मों में नये एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं। वह किसी भी बड़े चेहरे के साथ लंबे समय से नजर नहीं आये हैं। अक्षय एक सबजेक्टिव फिल्में बना रहे हैं जिसे वह अपने खुद के दम पर चलवाते हैं। गोल्ड में उन्होंने मौनी रॉय के साथ काम किया और पैड मैन में राधिका आप्टे के साथ। अरसे बाद अक्षय को किसी बड़ी स्टार के साथ काम करते देखा जाएगा।

फिल्म 'जुग जुग जीयो' की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री नीतू कपूर हुई कोविड-19 का शिकार

बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू कपूर ने बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने खुद को पृथक कर लिया है और फिलहाल वह बेहतर महसूस कर रही हैं। चार दिसंबर को कपूर परिवार के करीबी सूत्र ने बताया था कि चंडीगढ़ में फिल्म 'जुग जुग जीयो' की शीटिंग के दौरान 62 वर्षीया अभिनेत्री कोविड-19 से संक्रमित हो गई थीं। अपने अभिनेता-बेटे रणबीर कपूर द्वारा जरूरी इंतजाम किए जाने के बाद मुंबई लौटी नीतू कपूर ने आज इंस्टाग्राम पर अपने स्वास्थ्य के बारे में यह जानकारी साझा की।

उन्होंने एक बयान में कहा,फ्इस सप्ताह की शुरुआत में मैं कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी। उन्होंने कहा सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जा रहा है और तत्काल मदद के लिए मैं अधिकारियों का आभार व्यक्त करती हूं। मैं पृथकवास में हूं और अपने डॉक्टर की सलाह पर दवा ले रही हूं और फिलहाल बेहतर महसूस कर रही हूं।फ्र उन्होंने कहा,फ्कृपया सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ध्यान रखें।फ्र नीतू कपूर के अलावा फिल्म 'जुग जुग जीयो' के अभिनेता वरुण धवन और फिल्म निदेशक राज मेहता भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं।

शमा सिकंदर ने मानी आत्महत्या के प्रयास की बात, बताया डिप्रेशन और मानसिक स्थिरता के हालात से कैसे उबरीं

भारत में अब भी मानसिक बीमारी या डिप्रेशन जैसी समस्या के बारे में बात करने में लोग हिचकते हैं। फिर भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम सितारों ने अपनी ही कहानी साझा करके समाज में जागरुकता फैलाने का प्रयास किया है। इसी साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से इस मसले पर बहस और तेज हुई है। कई अन्य सितारों के साथ ही टीवी ऐक्ट्रेस शमा सिकंदर भी अपनी मानसिक समस्या को लेकर खुलकर बात करती रही हैं। यहां तक कि वह खुद स्वीकार करती हैं कि डिप्रेशन और मानसिक स्थिरता की वजह से एक बार उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था।

शमा सिकंदर करती हैं कि सौभाग्य था कि मैं इस स्थिति से बच गई और अगले 5 सालों में एक बड़े संघर्ष के बाद बीमारी से उबर गई। अपनी बीमारी को लेकर टाइम्स नाउ डिजिटल से बात करते हुए शमा सिकंदर ने कहा, 'यदि मैं 5 साल के संघर्ष से उबर सकती हूं तो फिर आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी डिप्रेशन और मानसिक स्थिरता की समस्या से बाहर निकल सकता है। आप इस समस्या का हल बाहर नहीं निकाल सकते। आपको खुद को समय देना होगा। आपको अपनी एनर्जी के बारे में विचार करना होगा। लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और दवा लेनी चाहिए।'

शमा सिकंदर ने इस समस्या को लेकर कहा कि आपके दिमाग के केमिकल्स में उतार चढ़ाव आता है और आप परेशानी महसूस करते हैं। आप अपनी स्थितियों से परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि यदि आप उबरना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अंधेरे के बाद आपको रोशनी भी जरूर नजर आएगी।

अजय देवगन की ये अधूरी ख्वाहिश जो अब करोड़ो खर्च करके भी कभी पूरी नहीं हो सकती...

ख्वाहिशों का अंत नहीं होता इंसान सपने देखता रहता है और उसे पूरा करने की कोशिश भी करता है। इन सपनों में से कुछ पूरे हो पाते हैं और कुछ नहीं। आम आदमी से लेकर बड़े-बड़े सेलेब्रिटी की भी बहुत सी ख्वाहिशें अधूरी है। तमाम पैसा होने के बाद भी वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते।

कुछ ऐसा ही अजय देवगन के साथ भी हुआ। अपने सफर की शुरूआत उन्होंने फिल्म फूल और कांटे से की थी। वह फिल्म काफी ज्यादा हिट हुई। अजय देवगन को फिल्म में उनके अभिनय के लिए काफी पसंद किया गया। धीरे-धीरे करके उन्होंने अपने लिए रास्ते खोजने शुरू किए। उन्होंने पहली सफलता के बाद कई हिट फिल्में दी। एक दौर ऐसा भी आया था जब उनकी कई फिल्में फ्लॉप भी हुई थी लेकिन ये जिंदगी का सफर था हार-जीत तो होगी। अजय देवगन ने हार नहीं मानी और वह लगातार मेहनत करते गये। अजय देवगन ने अपने अभिनय में काफी परिवर्तन किया और गंभीर फिल्में करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे उन्होंने एक्शन के साथ-साथ कॉमेडी में भी हाथ डाला और शानदार कॉमेडी करते हुए भी नजर आये। बॉलीवुड की दुनिया में आज अजय देवगन की एक अलग पहचान है।

इतना बड़ी पहचान बनाने के बाद अजय देवगन का एक सपना अधूरा रह गया और अब उस सपने के पूरा होने की सारी उम्मीदें भी टूट गयी है। अजय देवगन सिनेमा का सम्राट दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म करना चाहते थे। वह बचपन से ही दिलीप कुमार के फैन थे। अपने करियर में वह यह उपलब्धी हालिस करना चाहते थे। जब अजय देवगन फिल्मों में आये तब तक दिलीप कुमार ने ज्यादा फिल्में करना बंद कर दिया था। वह साल-दो साल में एक फिल्म में अभिनय करते थे। अजय देवगन को मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन अजय देवगन ने सीधे जाकर दिलीप कुमार जी से बात की और कहा कि मैं आपको लेकर फिल्म बनाना चाहता हूं। फिल्म करने के लिए दिलीप जी मान गये। अजय देवगन ने फिल्म के नाम का भी ऐलान कर दिया था। फिल्म का नाम असर - द इंपेक्ट रखा गया। किसी कारण ये फिल्म शुरू न हो सकी। वक्त बीतता गया और अजय की ये फिल्म धरी की धरी रह गयी। अब दिलीप कुमार की काफी उम्र हो गयी है। वह फिल्में नहीं कर सकते। वह घर में रहते है उनकी हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है। हाल ही में सायरा बानो ने दिलीप कुमार की हेल्थ के बारे में भी बात की और बताया की वह अब चीजे भूल जाते हैं। वह चल भी नहीं पाते। ऐसी हालत में काम करना किसी रूप में मुमकिन नहीं हैं। इस लिए अजय देवगन की यह ख्वाहिश अब कभी पूरी नहीं हो सकती।

राजा-महाराजा भी ऐसा आलीशान जीवन नहीं जीते होंगे जैसा प्रभास का है! जानें उनके घर की कीमत

सिनेमा के बाहुबली प्रभास आने वाले साल में तीन बड़ी फिल्में लेकर आने वाले हैं। बाहुबली और साहो के बाद अब प्रभास आदिपुरुष (रामायण) , राधे श्याम और सलार में जनर आने वाले हैं। ये तीनों फिल्में बड़े बजट की फिल्में हैं।

प्रभास का ये रुतबा पहले नहीं था। प्रभास की किस्मत को चमकाने का काम फिल्म बाहुबली ने किया। प्रभास के शानदार अभिनय ने उन्हें सिनेमा का बाहुबली बना दिया। पहले प्रभास साउथ इंडियन फिल्में करते थे तो एक सीमा तक ही सीमित होती थी। अब प्रभास को पूरी दुनिया जानती है।

अपनी मेहनत के दम पर बने प्रभास का लाइफ स्टाइल काफी आलीशान है। प्रभास को एक शानदार लाइफस्टान में रहना काफी पसंद है। साल 2014 में प्रभास ने हैदराबाद की सबसे मंहगी जगह जुबली हिल्स में आलीशान फार्म हाउस बनवाया। इस फार्म हाउस में वो सुविधाएं है जो एक 5 स्टार होटल में होती है। इस बंगले की कीमत 60 से 70 करोड़ की है। इस फार्म हाउस में जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर जैसी जिसे हैं।

इसके अलावा प्रभास के पास लग्जरी कई गाड़ियां है। उसकी पसंदीदी रोल्स रोल फैंटर कार है जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपये हैं। ये दुनिया की सबसे मंहगी कार में से एक हैं। प्रभास की जीवन शैली नोर्मल लाइफ स्टाइल से बिलकुल अलग है लेकिन उनके अभिनय में इतना दम है कि वह पर्दे पर एक मिट्टी के घर में रहने वाले इंसान का भी शानदार तरीके से किरदार निभा लेते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाएगा चीन, लॉन्च किया 2 सैटेलाइट

बीजिंग। चीन ने सिचुआन प्रांत के शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से बृहस्पतिवार को गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए दो उपग्रह प्रक्षेपित किए। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ग्रेविटेशन वेब हाइ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटरपार्ट ऑल स्काई मॉनिटर (जीईसीएएम) मिशन के दो उपग्रहों को तड़के एक लॉन्ग मार्च-11 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। जेईसीएएम के दो उपग्रहों का इस्तेमाल उच्च ऊर्जा वाले खगोलीय घटनाओं जैसे कि गुरुत्वाकर्षण तरंग गामा-किरणों के बिखराव, उच्च उर्जा वाले फास्ट रेडियो ब्रस्ट्स (कुछ समय के लिए रेडियो तरंगो जैसे दिखने वाले किरणों का बिखराव), विशेष गामा किरणों के बिखराव पर निगरानी रखने के लिए किया जाएगा तथा इसका मकसद न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स समेत कई अन्य चीजों और घटनाओं का अध्ययन करना है।

अमेरिका में कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष बनीं प्रमिला जयपाल

वाशिंगटन। भारतवंशी अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को अमेरिकी संसद के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस (सीपीसी) की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। सीपीसी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने से जयपाल अमेरिका में 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से होंगी। अमेरिका में यह पद प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है। भारत के चेन्नई में जन्मीं प्रमिला जयपाल (55) को बुधवार को सीपीसी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा कि सीपीसी रंगभेद को खत्म करने, गरीबी और असमानता को मिटाने जैसे कामों को प्रमुखता देगा और देश में परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा, ''मेरे सहयोगियों ने मुझे इतना महत्वपूर्ण ओहदा दिया है उससे मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं।'' जो बाइडन के प्रशासन में यह कॉकस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बाइडन (78) 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालने वाले हैं। जयपाल ने कहा कि हमारा कॉकस यहां के परिवारों के लिए राहत का काम करेगा। सीपीसी में 26 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक व्हिप समेत अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। भारतवंशी सांसद रो खन्ना को डिप्टी व्हिप चुना गया है और सांसद रशीदा तेलिब को उपाध्यक्ष चुना गया है।

कोरोना से अमेरिका का हाल-बेहाल, 24 घंटे में रिकॉर्ड 3219 की मौत

वाशिंगटन। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के अनुसार अमेरिका में बुधवार को 3,054 लोगों की संक्रमण से मौत हुई,जो अब तक की एक दिन में सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले सात मई को 2,769 लोगों की संक्रमण से मौत हुई थी। देश में बुधवार को 18 लाख नमूनों की जांच की गई। देश में संक्रमण के 210,000 मामले हैं और 106,688 लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित देश है और यहां संक्रमण से बचाव के लिए कम से कम दो टीकों को मंजूरी जल्द मिल सकती है।

स्पेन के बादालोना में एक इमारत में लगी आग, 17 लोग झुलसे; 2 की गंभीर हालत

बार्सिलोना(स्पेन)। पूर्वोत्तर स्पेन के बादालोना में एक इमारत में आग लगने से कम से कम 17 लोग झुलस गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। इस इमारत में कुछ लोग अवैध रूप से रह रहे थे। दमकलकर्मियों ने बुधवार रात को बताया कि उन्होंने इमारत की खिड़कियों से करीब 30 लोगों को बाहर निकाला। दमकल विभाग के प्रमुख डेविड बोरेल ने कहा कि दमकलकर्मी इमारत के खाली होने की पुष्टि कर पाते, उससे पहले ही छत गिर गई, जिसके कारण तलाश अभियान जारी रखना असंभव हो गया, क्योंकि आग तब तक बुझी नहीं थी। अधिकारियों ने अनुमान जताया कि आग को बुझाने में कई और घंटे लगेंगे। बादालोना के मेयर जेवियर गार्सिया अल्बिओल ने बताया कि इमारत में 100 से अधिक लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, जिनमें से 60 का पता चल गया है।

चौथी बार नीलाम होगा डोनाल्ड ट्रंप के बचपन का घर, जानिए कितने रुपये तय की गई है कीमत

न्यूयॉर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बचपन का घर चार साल में चौथी बार नीलाम किया जा रहा है। इसकी कीमत 3 मिलियन डालर (करीब 22 करोड़ भारतीय रुपये) तय की गई है। नीलाम करने वाली कंपनी को उम्मीद है कि ट्रंप के प्रशंसक इसको खरीदने में सफल होंगे। ट्रंप के स्वर्गीय पिता फ्रेड ने न्यूयॉर्क के उपनगर की जमैका स्ट्रीट में यह घर बनवाया था। इस घर में ट्रंप का चार साल की उम्र तक बचपन बीता था। घर में पांच बेडरूम हैं। बाद में फ्रेड ने बड़ा घर बनवा लिया था, जिसमें 23 कमरे थे। ट्रंप का यह घर चौथी बार नीलाम हो रहा है। इससे पहले इस घर की 2016 में नीलामी हुई थी। घर वहीं पास में रहने वाले व्यक्ति ने लिया था। एक साल बाद नीलामी में बोली लगाने वाले ने लेने से इन्कार कर दिया।

चीन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने की है चिनफिंग की चाहत: पोंपियो

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग न सिर्फ घरेलू मामलों पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं बल्कि अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बनाना चाहते हैं। इसलिए चीनी नेता योजना के तहत सैन्य शक्ति बढ़ाने के साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जोड़-तोड़ भी कर रहे हैं।

पोंपियो ने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक कार्यक्रम में बुधवार को कहा, 'चिनफिंग ने अपने इरादों को स्पष्ट तौर पर जाहिर कर दिया है। वह जो कुछ कहते हैं, उसे आपको सिर्फ सुनना पड़ता है। उनका कहना है कि वह अपने देश पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं और चीन को विदेश में नंबर एक ताकत बनाने के इच्छुक हैं। वह इसी दिशा में काम कर रहे हैं।'

अमेरिकी विदेश मंत्री के अनुसार, 'वह (चिनफिंग) चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को मजबूत कर रहे हैं। वह बीजिंग के फायदे के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जोड़-तोड़ भी कर रहे हैं। वह दुनियाभर में प्रभाव डालने वाले व्यापक अभियान में व्यस्त हैं।' 67 वर्षीय चिनफिंग चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव के साथ ही केंद्रीय सैन्य आयोग के चेयरमैन भी हैं। वर्ष 2018 में चीन के संसद ने इस पद के लिए सीमित कार्यकाल को खत्म कर दिया जो दो सालों का था। इसके बाद अब चिनफिंग इस चेयरमैन के पद को ताउम्र संभालेंगे। उन्होंने कहा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन न केवल चीनी नागरिकों बल्कि अमेरिकी विद्यार्थियों, प्रोफेसरों को भी निशाना बनाना चाहते हैं।

वर्ष 2018 में चीनी संसद के जरिये उस प्रावधान को खत्म कर दिया था, जिसके तहत कोई व्यक्ति सिर्फ दो कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रह सकता था। इस प्रावधान के खत्म होने से चिनफिंग आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं। पोंपियो ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी जानती है कि वह अमेरिकी रिसर्च, खोज और तकनीक की बराबरी नहीं कर सकती है। इसलिए उसकी तकनीक चोरी या दूसरे देशों से खरीद पर आधारित है।

गुलाम कश्मीर के नेता बोले, किसानों के जरिये भारत को अशांत करने की कोशिश बंद करे पाकिस्तान

ग्लासगो (एजेंसी)।

पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी के भारत संबंधी बयान पर पाकिस्तानी कब्जे वाले गुलाम कश्मीर के राजनीतिक नेता डॉ. अमजद अयूब मिर्जा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा है कि भारत के किसानों के आंदोलन की चिंता करने की जगह फवाद 13 दिसंबर की संयुक्त विपक्ष की सरकार विरोधी लाहौर रैली की चिंता करें। वह भारत को अशांत करने के लिए भारतीय किसानों को भड़काने की कोशिश न करें।

अक्सर भारत विरोधी बयान देने वाले फवाद ने कहा था कि उनका दिल सीमापार आंदोलन कर रहे पंजाबी किसानों के लिए धड़क रहा है। सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर भारत सरकार को हृदयहीन बताया था। ब्रिटेन में रहकर गुलाम कश्मीर के हित की लड़ाई लड़ रहे मिर्जा ने कहा, चौधरी यह ड्रामा किसी और समय करें। पहले अपने देश के हालात देखें, जहां विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है। पाकिस्तान खुद तमाम समस्याओं से जूझ रहा है।

हाथ पर हाथ धरे बैठी है पाकिस्तान की सरकार

गुलाम कश्मीर के नेता ने कहा, इमरान सरकार को समस्याओं से निपटने का कोई तजुर्बा नहीं है। इसीलिए वह सरकार विरोधी भावनाओं को काबू करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उसे सूझ नहीं रहा कि वह विपक्ष की एकजुटता से निपटने के लिए क्या करे।

मिर्जा को फवाद के उस बयान की याद दिलाई, जिसमें पुलवामा में 40 भारतीय जवानों की शहादत पर कहा गया था- हमने हिंदुस्तान में घुसकर मारा है। मिर्जा ने कहा, यह वही व्यक्ति है, जिसने संसद में खड़े होकर स्वीकार किया कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान था और उसे इसके लिए गर्व है। अब वही व्यक्ति दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है। जाहिर है किसान आंदोलन के जरिये पाकिस्तान भारत को अशांत करने की कोशिश कर रहा है।

AIIMS के सर्वे में हुआ खुलासा, केवल 53प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी ही करते हैं हाथ की स्वच्छता का पालन

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

कोरोना के सभी दिशानिर्देशों के बावजूद केवल 20 स्वास्थ्यकर्मी ही 20 सेकंड तक हाथ धोते है। एम्स के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा अगस्त में एक महीने तक किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि कोविड-19 से बचाव के लिए अभी भी कई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 20 सेंकड तक हाथ धोने की प्रक्रिया को सीखना होगा। सर्वे के मुताबिक, 956 सर्वेक्षणों में से, 47/ उचित हाथ स्वच्छता का पालन नहीं करते है वहीं लगभग 32त्न रोगियों के संपर्क के बाद अपने हाथों की सफाई नहीं करते हैं।

डॉ पीयूष रंजन ने टीओआई को बताया, 'हमारे अनुभव से पता चला है कि स्वास्थ्य कर्मियों को समय की कमी है।' इस सर्वेक्षण में सरकार के साथ-साथ निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया था, और यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। इस सर्वे में बड़े अस्पतालों से लेकर छोटे औषधालयों तक को रखा गया था। इस सर्वे से पता चला कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता कम जोखिम वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक जोखिम में पाए गए। सर्वेक्षणों में से आधे से अधिक ने सहयोगियों (58/), काम करने वाले (58/) या खाने (53/) के साथ बातचीत करते समय सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए नहीं रखा।

वहीं 79/ लोगों को हाथ नहीं मिलाना याद रहा। इसको लेकर लैप्स के लिए जगह की कमी, पीपीई में दूसरों से बात करने में कठिनाई, बदलती आदतों में कठिनाई और ज्ञान की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस सर्वे के अनुसार, कोरोना की चपेट में आने वाले सबसे बड़ा जोखिम मोबाइल फोन को माना गया है। केवल 59 फीसदी ही ड्यूटी के बाद फोन का इस्तेमाल करते है वहीं कोरोना मरीजों को देखने वाले डॉक्टर अपने फोन को साथ में रखते हुए आइसीयू जा रहे है और फिर वहां से अपने घर। रिसर्च को प्रकाशित करने वाली पत्रिका 'डायबिटीज एंड मेटाबोलिक सिंड्रोमः क्लिनिकल रिसर्च एंड रिव्यू' के मुख्य संपादक डॉ अनूप मिश्रा ने कहा, 'डॉक्टर एक ही मोबाइल फोन को आईसीयू और उनके घरों में ले जा रहे हैं।'

इस देश में तीन भारतवंशी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया गया स्मारक

जोहानिसबर्ग। (एजेंसी)।

दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशी स्वतंत्रता सेनानियों शिरीष नानाभाई, रेगी वंदेयर और इंद्रेश नायडू की याद में स्मारक बनाया गया है। रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले वंदेयर का 84 साल की उम्र में 2015 में निधन हो गया जबकि नानाभाई और नायडू का क्रमशः 78 और 80 साल की उम्र में 2016 में निधन हुआ। गैर सरकारी संगठन अहमद कठराडा फाउंडेशन (एकेएफ) ने वेस्टपार्क में दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिकारी नेता लालू 'इसू' चीबा के समाधि स्थल पर तीनों नेताओं की याद में स्मारक बनाया है। रंगभेद के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण चारों नेताओं को 1961 में गिरफ्तारी के बाद रोबेन जेल में एक दशक तक रहना पड़ा था।

एकेएफ बोर्ड के सदस्य इस्माईल वादी ने बताया कि जिन लोगों को याद किया जा रहा है वे बेहद साधारण लोग थे और वे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अभियान में शामिल हुए थे तथा सबके लिए प्रेरणास्रोत बन गए। वादी ने कहा, ''रेगी वेटर थे, शिरीष एक स्टोर में काम करते थे और इंद्रेश सामान्य कामकाजी व्यक्ति थे लेकिन उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाया और अपने समय में महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बन गए।'' तीनों स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों ने लोकतंत्र के लिए उनके योगदान से जुड़ी यादें साझा कीं। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए दक्षिण अफ्रीका नेशनल डिफेंस फोर्स के पूर्व जनरल शिफिवी न्यंडा ने कहा, ''उनकी गैरमौजूदगी के बावजूद आज भी हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। वे हमारे लिए पथप्रदर्शक की तरह हैं।

पाक पीएम इमरान खान ने विपक्षी पार्टी को दी चुनौती, कहा- 'मेरे खिलाफ संसद में लाकर दिखाए अविश्वास प्रस्ताव'

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्षी गठबंधन को चुनौती दी है कि वह उन्हें अपदस्थ करने के लिए संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर दिखाए। खान ने विपक्ष की उस मांग की निंदा की जिसमें उसने उन्हें मध्यावधि चुनाव के लिए विवश करने के वास्ते सांसदों से सामूहिक इस्तीफा देने को कहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश को विभिन्न संकटों से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय चर्चा कराने से कभी पीछे नहीं हटे हैं।

ग्यारह दलों वाले विपक्षी गठबंधन ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उनके सांसद सरकार को पंगु बनाने और प्रधानमंत्री को मध्यावधि चुनाव के लिए विवश करने के वास्ते इस महीने के अंत तक सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। यह फैसला विपक्षी गठबंधन 'पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट' (पीडीएम) की इस्लामाबाद में हुई मैराथन बैठक में लिया गया। खान के नेतृत्व वाली सरकार को अपदस्थ करने के लिए 11 विपक्षी दलों के इस गठबंधन की स्थापना इस साल सितंबर में हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को अपदस्थ करने का संवैधानिक रास्ता संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने का है। उन्होंने कहा, ''यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो वह आए और विधानसभाओं में भी ऐसा करे।'' खान ने सांसदों से सामूहिक इस्तीफे के आह्वान को लेकर विपक्ष की आलोचना की।

क्या अमेरिका में कोविड-19 के लिए फाइजर के टीके को मिलेगी हरी झंडी?

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

कोविड-19 के लिए फाइजर के टीके को अमेरिका में हरी झंडी पाने के लिए एफडीए के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की चर्चा के दौर की बड़ी बाधा को पार करना होगा। अगर एफडीए टीके को मंजूरी दे देता है तो देश में इसे सुरक्षित और प्रभावी मानकर इसका उपयोग शुरू किया जाएगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (एफडीए) की टीका सलाहकार समिति की बृहस्पतिवार को हो रही बैठक अमेरिका में फाइजर के टीके के उपयोग को मंजूरी देने के लिहाज से संभवतः एक पड़ाव है। परीक्षण के दौरान टीका काफी हद तक कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव करने में प्रभावी साबित हुआ है। एफडीए का यह पैनल एक साइंस कोर्ट की तरह काम करता है और यह टीके से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेगा।

चर्चा का सीधा प्रसारण किया जाता है। ज्यादातर मामलों में एफडीए गैर-सरकारी विशेषज्ञों की इस समिति की सलाह को मानता है, हालांकि उसके लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों, दुनिया में 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, अकेले अमेरिका में 2,89,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत होने की पृष्ठभूमि में एफडीए का टीके के उपयोग पर फैसला आने वाला है। हालांकि, इस बैठक में ब्रिटेन में टीकाकरण के दौरान दो लोगों को हुए इसके प्रतिकूल प्रभावों (रिएक्शन) के मामले पर भी चर्चा होगी क्योंकि ब्रिटिश सरकार इसकी जांच कर रही है। वहीं ब्रिटिश अधिकारियों ने गंभीर बीमारी से ग्रस्त या अतीत में गंभीर बीमारी की चपेट में आए लोगों को टीका लगाने को लेकर चेतावनी दी है। इसके बावजूद एफडीए से टीके को जल्दी मंजूरी मिलने की संभावना है क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में पैनल की बैठक में इसके प्रति सकारात्मक रूख रहा है।

एफडीए का कहना है कि बड़े पैमाने पर किया गया फाइजर का अध्ययन बताता है कि जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर विकसित किया गया उसका यह टीका सभी लोगों पर 90 प्रतिशत से ज्यादा प्रभावी है। सुरक्षा संबंधी कोई बड़ी मसला सामने नहीं आया है और टीके से जुड़े सामान्य साइड इफेक्ट जैसे बुखार, थकान और इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द आदि को बर्दाश्त किया जा सकता है। जॉन हॉप्किंस यूनिवर्सिटी के 'इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर' के प्रमुख डॉक्टर विलियम मूस का कहना है, ''रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि हमने पहले सुना था और यह उत्साहित करने वाले हैं।'' उन्होंने कहा, ''मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा जिससे टीके की मंजूरी में देरी हो सकती है।'' इस संबंध में एफडीए के कमिश्नर स्टीफन हान ने एक साक्षात्कार में कहा, ''बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं कि इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है या क्या हम पूरी क्षमता के साथ प्रयास कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''मैं आशा करता हूं कि लोग हमारी पारदर्शिता को देखेंगे और समझेंगे कि हमने कितनी मेहनत की है।

सार समाचार

जेपी नड्डा के काफिले पर हमला चिंताजनक: जगदीप धनखड़

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य प्रशासन उनकी चेतावनियों के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहा। राज्यपाल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस बारे में सतर्क किया था कि डायमंड हार्बर में भाजपा की बैठक के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी दिक्कत पैदा हो सकती है। धनखड़ ने ट्वीट में लिखा कि मुख्य सचिव ने उन्हें सूचित किया थ कि पुलिस महानिदेशक को आगाह कर दिया गया है और तदनुसार अवगत करा दिया गया है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ''घटना से कानूनी प्राधिकार के पूरी तरह विफल होने का संकेत मिलता है।'' भाजपा सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि नड्डा के काफिले पर बुधवार को तब हमला हुआ जब वह भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने डायमंड हार्बर जा रहे थे। इसमें पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता घायल हो गए। भगवा दल ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया है।

अखिलेश बोले, सरकार के सभी फैसलों में होनी चाहिए आम जनता की भागीदारी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसान आंदोलन भारत के इस लोकतांत्रिक मूल्य की पुनर्स्थापना का भी आंदोलन है कि सरकार के सभी फैसलों में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, ''किसान आंदोलन भारत के इस लोकतांत्रिक मूल्य की पुनर्स्थापना का भी आंदोलन है कि सरकार के सभी फैसलों में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए; सरकार की मनमानी नहीं और इसी लिए भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का हर नागरिक आज किसान आंदोलन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता जा रहा है। सपा नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। इस आंदोलन के समर्थन में अखिलेश और पार्टी कार्यकर्ता सोमवार को सड़कों पर भी उतरे थे और धरना प्रदर्शन भी किया था। इस मामले में अखिलेश और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गौतम पल्ली पुलिस थाने में मामला भी दर्ज हुआ था।

जम्मू कश्मीर के बडगाम में जैश आतंकी गिरफ्तार, पिस्तौल और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तारिक अहमद भट्ट को बुधवार देर रात 'नाका' जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उसके पास से एक पिस्तौल और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। भट्ट इस साल सितंबर में आतंकवादी संगठन में कथित तौर पर शामिल हो गया था।

जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स को कोविड-19 के टीके के क्लीनिकल परीक्षण की सशर्त स्वीकृति मिली

नयी दिल्ली। भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने पुणे की जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके का मानव पर पहले और दूसरे चरण का क्लीनिकल परीक्षण करने की सशर्त मंजूरी दे दी है। दवा कंपनी जेनोवा, अमेरिकी कंपनी एचडीटी बायोटेक कॉरपोरेशन के सहयोग से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टीका विकसित कर रही है। दवा कंपनी ने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण के लिए अनुमति मांगी थी। कोविड-19 के संबंध में विषय के विशेषज्ञों की कमेटी (एसईसी) की सिफारिशों को डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। एसईसी की सिफारिश में कहा गया, ''विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कमेटी ने पहले और दूसरे चरण के क्लीनिक परीक्षण की मंजूरीदी है। पहले चरण के परीक्षण के बाद कंपनी को अध्ययन के आंकड़ों को पेश करना होगा।

महाराष्ट्र के 'शक्ति अधिनियम'में मौत की सजा, मुकदमे की त्वरित सुनवाई का होगा प्रावधान

मुंबई। महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान हैं। प्रस्तावित कानून को राज्य में लागू करने के लिये विधेयक के मसौदे में भादंसं, सीआरपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी और इसे आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। विधानमंडल का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के लिए आएगा।

स्थिति को पेचीदा बनाने वाली गतिविधियों से बचने की जरूरत: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

नयी दिल्ली।(एजेंसी)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के आक्रामक सैन्य बर्ताव के संदर्भ में बृहस्पतिवार को कहा कि गतिविधियों में संयम बरतने और स्थिति को और पेचीदा बनाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने से क्षेत्र में सतत शांति बनाए रखने में मदद मिल सकती है। रक्षा मंत्री आसियान के रक्षा मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक 'एडीएमएम-प्लस' को संबोधित कर रहे थे। 'एडीएमएम-प्लस' आसियान देश और भारत,चीन समेत आठ संवाद भागीदारों का एक मंच है। अधिकारियों ने बताया कि चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघेई भी इस ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए।

सिंह ने ''वर्तमान क्षेत्रीय माहौल और दिखाई देने वाली तल्खी'' पर अपने विचार रखे और एशिया में बहुलवादी और सहयोगात्मक सुरक्षा क्रम के वास्ते वार्ता और सहयोग को बढ़ावा देने में आसियान नीत मंचों की केन्द्रीय भूमिकाओं की सराहना की। उन्होंने कहा,'' जिस समय हम आपसी विश्वास और भरोसा बढ़ा रहे हैं, ऐसे में स्थिति को और पेचीदा बनाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने और गतिविधियों में संयम बरतने से क्षेत्र में शांति बनाने में मदद मिलेगी।'' सिंह की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सात महीने से अधिक समय से सीमा पर जारी विवाद की पृष्ठभूमि और दक्षिण चीन सागर तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों के बीच आई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों, खुलेपन और समावेशिता पर आधारित चुनौतियों से मिलकर निपटने की क्षमता क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे।

सिंह ने कहा, ''नियम आधारित व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा, साइबर संबंधी अपराध एवं आतंकवाद जैसे कई खतरे हैं, जो चुनौतियां बने हुए हैं और हमें एक मंच के तौर पर इनसे निपटने की आवश्यकता है।'' उन्होंने कहा, ''वसुधैव कुटुबंकम जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है और सर्वे भवंतु सुखिना अर्थात सर्वत्र शांति हो, भारतीय सभ्यता का मूल है। इसलिए समावेशिता, समानता और खुलापन इस सिद्धांत में समाहित है। रक्षा मंत्री ने जैव आतकंवाद, देशों के बीच तस्करी और महामारी के खतरों से निपटने के लिए सतत प्रयास करने की अपील की। साथ ही साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौती से मिल कर निपटने की भी बात कही।

पीएम मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है: योगी

गोरखपुर (उप्र)। (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पिछले पांच-सात साल से देश बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी तक कोरोना वायरस का टीका आ जाने की उम्मीद है, तब तक कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के मानकों का पहले की तरह की पालन किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को महाराणा प्रताप (एमपी) शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में कहा, ''वैश्विक महामारी के अप्रत्याशित संकट के दौरान प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो असाधारण कार्य हुए हैं, वे प्रौद्योगिकी से ही सम्भव थे।''

उन्होंने छात्रों से प्रौद्योगिकी से जुड़कर इसका बेहतर उपयोग करने की अपील की। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी उपस्थित थे। समारोह में आदित्यनाथ एवं दीक्षित ने महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैद्यनाथ की स्मृति में लिखी पुस्तक 'भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रसार' का विमोचन किया।

दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया

नयी दिल्ली।(एजेंसी)।

दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर यहां बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। इससे एक दिन पहले भाजपा नेताओं ने महापौर और पार्टी नीत नगर निगमों के नेताओं की ''हत्या की साजिश'' का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तीनों नगर निगम...उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) - के बकाए का भी भुगतान करने की मांग राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी सरकार से की।

भाजपा की दिल्ली इकाई ने बुधवार को एक वीडियो क्लिप का हवाला देते हुए सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के खिलाफ भाजपा शासित नगर निगमों के नेताओं की ''हत्या की साजिश'' का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पाठक ने इन आरोपों को बकवास बताया और कहा कि भाजपा लोगों की छवि धूमिल करने के लिए दुष्प्रचार करती रहती है। पार्टी की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा ने कहा,'' हम अपने महापौर की हत्या की साजिश के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि भाजपा इस प्रकार की चुनौतियां का जवाब देना जानती है।''

प्रदर्शन में भाजपा युवा और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सदस्य भी शामिल हुए और उन्होंने मथुरा रोड स्थित सिसोदिया के आवास के निकट पुलिस अवरोध को पार करने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे देवराहा ने दावा किया कि पुलिस ने भाजपा के चार से पांच कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस थाने ले गए हैं। उन्होंने कहा,'' महापौर और निगम के अन्य नेता चार दिन से मुख्यमंत्री के आवास के बाहर ठंड में धरना दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान नहीं कर रही है। इससे सफाई कर्मचारियों, चिकित्सकों और नर्सों का वेतन देने में दिक्कतें आ रही हैं,जो कोरोना योद्धा के तौर पर लोगों को सेवाएं दे रहे हैं।

सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा नया संसद भवन: ओम बिरला

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के नये भवन के शिलान्यास के अवसर पर बृहस्पतिवार को कहा कि यह भवन सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा तथा देश की जनता के लिए प्रेरणा का केंद्र भी होगा। बिरला ने नए दोनों सदनों के सदस्यों की इच्छा के मुताबिक नये संसद भवन के निर्माण की मंजूरी देने और शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, ''आज देश के लिए गौरव का दिन है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती के स्तंभ संसद के नये भवन के शिलान्यास के मौके पर समस्त देशवासियों का स्वागत करता हूं।'' वर्तमान संसद भवन का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा ''हमारे वर्तमान संसद भवन का निर्माण 1927 में हुआ था। हमारी संसद लोगों के विश्वास और अकांक्षाओं का प्रतीक है। संसद भवन देश की आजादी, संविधान सभा और अनेक कानूनों के बनने की साक्षी रही है।'' उनके अनुसार, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की इच्छा थी कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए नये भवन की जरूरत है और प्रधानमंत्री ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। बिरला ने कहा, ''हम आजादी के 75 साल पूरा करने जा रहे हैं। देश की जनता का सपना है कि उन्हें संसद का नया आधुनिक भवन मिले।'' उन्होंने कहा, ''मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही आधुनिक तकनीक युक्त, सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण करेंगे जहां जन प्रतिनिधि जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को कुशलता एवं दक्षता के साथ पूरा कर पाएंगे।'' लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, '' नया संसद भवन सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी होगा।'' इस अवसर पर आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, ''यह सिर्फ भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं, विश्व में लोकतंत्र की परंपरा के लिए बड़ा दिवस माना जाएगा।'' उन्होंने कहा, ''लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने 2019 में नए संसद भवन को लेकर एक संकल्प भी पारित कराया जिसका बहुत ही महत्व है।''

गरीबों के कर्ज लेने के दावे वाली खबर का हवाला देते हुए बोले राहुल, गरीबों के मौलिक अधिकार छीन रही है सरकार

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों के कर्ज लेने के दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीब लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही है। उन्होंने ट्वीट किया, ''मोदी सरकार ग़रीबों के मौलिक अधिकार छीन रही है। ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। देश के बेहतर भविष्य के लिए हमें हर वर्ग के अधिकारों का सम्मान करना ही होगा।'' कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया उसमें एक सर्वेक्षण के आधार पर दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान 11 राज्यों में करीब 45 फीसदी लोगों को भोजन के लिए कर्ज लेना पड़ा।

हज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ाई गई: मुख्तार अब्बास नकवी

नयी दिल्ली / मुंबई।(एजेंसी)।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बृहस्पतिवार को बताया कि हज-2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 10 जनवरी तक कर दिया गया है और साथ ही हज यात्रियों के अनुमानित खर्च में भी कमी की गई है। नकवी के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, उन्होंने मुंबई में हज कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि हज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर थी जिसे बढ़ा कर 10 जनवरी, 2021 कर दिया गया है। उन्होंने बताया, 'अब तक 40 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा बिना 'मेहरम' के हज के लिए 500 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं।'

मंत्री के मुताबिक, हज 2020 के लिए 2100 से अधिक महिलाओं ने बिना मेहरम (पुरुष रिश्तेदार) के हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, ये महिलाएं इस बार हज पर जा सकेंगी। बिना मेहरम के हज पर जाने वाली महिलाओं के, हज 2020 के लिए किये गए आवेदन हज 2021 के लिए भी मान्य रहेंगे। उन्होंने कहा कि नए आवेदन करने वाली महिलाओं को भी हज 2021 पर बिना लॉटरी के जाने की व्यवस्था की गई है। हज के लिए आवेदन, ऑनलाइन और मोबाइल एप्प के जरिये एवं ऑफलाइन माध्यम से किये जा रहे हैं। नकवी ने कहा, 'इम्बार्केशन प्वाइंट (प्रस्थान स्थल) के अनुसार हज 2021 के खर्च के आकलन एवं सऊदी अरब से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रति हज यात्री सम्भावित खर्च भी कम किया गया है। वर्तमान आंकलन के मुताबिक, अहमदाबाद और मुंबई इम्बार्केशन प्वाइंट से जाने वाले हज यात्रियों को लगभग 3 लाख 30 हजार रूपये; बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद इम्बार्केशन प्वाइंट से जाने वाले हज यात्रियों को लगभग 3 लाख 50 हजार रूपये खर्च करने होंगे।' उनका कहना है कि कोच्चि एवं श्रीनगर इम्बार्केशन प्वाइंट से जाने वाले हज यात्रियों को लगभग 3 लाख 60 हजार रुपये; कोलकाता इम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले हज यात्रियों को लगभग 3 लाख 70 हजार रूपये और गुवाहाटी इम्बार्केशन प्वाइंट से जाने वाले हज यात्रियों को लगभग 4 लाख रूपये प्रति हज यात्री खर्च करना होगा।

किसान संगठन सरकार के प्रस्तावों पर विचार करें, हम आगे बातचीत के लिये तैयार हैं: नरेंद्र तोमर

नई दिल्ली।(एजेंसी)।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों के नेताओं से सरकार द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर विचार करने का बृहस्पतिवार को एक बार फिर आग्रह किया और कहा कि सरकार उनके साथ आगे और बातचीत करने के लिये तैयार है। किसानों ने एक दिन पहले ही सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बनाये रखने के बारे में लिखित आश्वासन देने और नये कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन की पेशकश की है। तोमर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''नये कृषि कानूनों में किसानों को जहां कहीं भी कोई आपत्ति है, हम खुले दिमाग से उस पर विचार करने के लिये तैयार है। हम किसानों की सभी शंकाओं को दूर करना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम किसान नेताओं से सुझाव मिलने की प्रतीक्षा करते रहे ताकि उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके लेकिन वह कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं।''

पिछले करीब दो सप्ताह से किसानों का नये कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है। किसान राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वह तीन नये कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की मांग कर रहे हैं। तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिये हर समय तैयार है और आगे भी तैयार रहेगी। उन्होंने कहा, ''ठंड के इस मौसम में कोविड- 19 महामारी के बीच किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर हम चिंतित हैं।किसान संगठनों को सरकार के प्रस्तावों पर जल्द से जल्द विचार कर लेना चाहिये जिसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो हम मिलकर अगली बैठक के बारे में फैसला कर लेंगे।'' सरकार ने बुधवार को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था के जारी रहने को लेकर लिखित आश्वासन देने का प्रस्ताव भेजा था। सरकार ने कहा कि एमएसपी व्यवस्था जारी है और जा रहेगी।

हालांकि, किसान संगठनों ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया और कहा कि तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लिये जाने की अपनी मांग को वह आंदोलन तेज करेंगे। एमएसपी पर नये कानून के बारे में पूछे जाने पर तोमर ने कहा कि नये कृषि कानूनों का एमएसपी व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमएसपी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने किसानों से बातचीत के मेज पर लौटने का आग्रह करते हुये कहा कि सरकार की तरफ से जो पेशकश की गई है उन पर वह विचार करें। सरकार उनमें भी यदि कोई मुद्दा है तो उस पर बातचीत के लिये तैयार है। तोमर ने कहा कि ऐसे समय जब बातचीत चल रही है और सरकार आगे भी बातचीत के लिये तैयार है विरोध प्रदर्शन को तेज करना उचित नहीं है। किसानों की सभी समस्याओं और चिंताओं पर बातचीत के लिये सरकार तैयार है। कृषि मंत्री ने विश्वास जताया कि बातचीत से कोई न कोई समाधान निकल आयेगा।

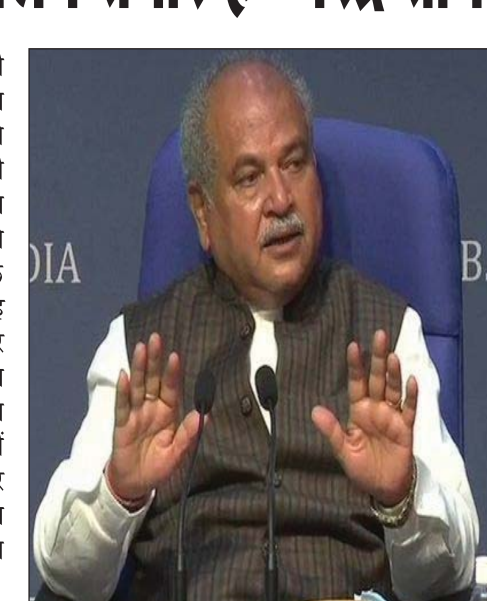

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सूरत में कॉलेज जा रही एक लड़की पर बलात्कार, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिला,

क्रांति समय संवाददाता

सूरत में संदिग्ध अवस्था में पाई गई इस युवती के साथ बलात्कार किया गया है। युवती अपने होश में आ गई है लेकिन वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। युवती का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लिंबायत के गोडादरा इलाके की एक १८ वर्षीय युवती कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भरने के लिए घर से निकली और गायब हो गई। जिसके बाद उन्हें उस रात दस बजे पारले पॉइंट के पास एक अर्ध-चेतन अवस्था में पाया गया था। लड़की के गुप्तांग से खून बह रहा था और सिर पर चोट लगने की बात भी कही जा रही थी। युवती को उपचार के लिए १०८ के माध्यम से सिविल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के बाद युवती होश में आई है। लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर है। और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस जांच में शामिल हुए कि युवती के साथ बलात्कार हुआ था। गोकुलधाम अपार्टमेंट सूरत के एक पॉश इलाके पार्ले पॉइंट में पाया गया है और इस अपार्टमेंट की पार्किंग में एक १८ वर्षीय छात्र पाया गया था। लिंबायत क्षेत्र की एक १८ वर्षीय युवती प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए वेसू क्षेत्र के अग्रवाल कॉलेज गई थी। और तब से फोन बंद है और फोन चालू है। जिससे परिवार चिंतित हो गया। और अंत में लिम्बायत पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस भी मुस्तैद थी। लेकिन कोई लिंक नहीं लिया गया। लेकिन अचानक पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आया और पुलिस के होश उड़ गए। लापता छात्र पारले पॉइंट के गोकुलधाम अपार्टमेंट की पार्किंग में घायल पाया गया था।बच्ची को इलाज के लिए तुरंत सिविल अस्पताल भेज

सूरत के लिंबायत ने गोडादरा क्षेत्र की एक १८ वर्षीय युवती जो फॉर्म भरने के लिए कॉलेज जाने के लिए घर से निकले के बाद लापता हो गई थी, करीब १० बजे पारले पॉइंट के पास बेहोशी अवस्था में मिली। युवती को इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया।

पुलिस कर्मियों को सकारात्मक रहने और सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया -पीएसआई अमिता जोशी

क्रांति समय संवाददाता

सुरत शहर के उधना पुलिस

स्टेशन में कार्यरत महिला पीएसआई अमिता जोशी की आत्महत्या करने के बाद एक वीडियो सोशल मिडिया में वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस कर्मियों को सकारात्मक रहने और सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया उनके करीबी कर्मचारी और दोस्त आत्मविश्वासी महिला पीएसआई अमिता जोशी की आत्महत्या से उबर नहीं पाए। अमिता जोशी का एक ५.४२ मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जिसमें वह नए पुलिस कर्मियों को सकारात्मक होने और कविता के छंदों के माध्यम से अपने अनुभव के माध्यम से सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

पीएसआई ने किया विवाहिता से दुष्कर्म प्रयास, क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

क्रांति समय संवाददाता

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने साइबर क्राइम के पीएसआई को एक विवाहित महिला के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप गिरफ्तार कर लिया। साथ ही विवाहिता को धमकाने वाले अन्य पीएसआई के खिलाफ जांच की जा रही है। एक साल पुरानी इस घटना की बात करें तो ७ अक्टूबर २०१९ को विवाहिता अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने अहमदाबाद के वाडज पुलिस थाने गई थी। जहां उसकी मुलाकात पीएसआई आरआर मिश्रा से हुई। पीएसआई ने विवाहिता से उसका नंबर ले लिया और उसे वॉट्सएप और कॉल करने लगा। एक दिन पीएसआई ने विवाहित को शहर के आश्रम रोड स्थित एक होटल में बुलाया।

जहां पीएसआई ने विवाहिता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। हांलाकि विवाहिता किसी प्रकार वहां से भाग निकली। अन्य एक पीएसआई ने घटना के बारे में पुलिस फरियाद नहीं करने की विवाहिता को धमकी दी थी।

लेकिन विवाहिता ने वाडज पुलिस थाने में पीएसआई आरआर मिश्रा के खिलाफ रपट दर्ज करवा दी। बाद में १५ जुलाई २०२० को मामले की जांच क्राइम ब्रांच के एसीपी डीपी चूडास्मा को सौंप दी गई। जांच में पुख्ता सबूत और उस वक्त का एक गवाह मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी पीएसआई आरआर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया7 जबकि अन्य पीएसआई के खिलाफ जांच कर रही है।

मुख्यमंत्री का राज्य की ६ मनपा के आयुत्तों को रोजाना के कार्य संभालने का आदेश

क्रांति समय संवाददाता मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य की ६ महानगरपालिका (मनपा) के निर्वाचित महापौर और पार्षदों का कार्यकाल १३ दिसंबर, २०२० को पूरा होने से आगामी सामान्य चुनावों के संपन्न होने तक इन महानगरपालिकाओं के प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर वर्तमान में कार्यरत मनपा आयुत्तों को इन निकायों के रोजाना के कार्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश जारी किया है। उपरोक्त आदेशानुसार अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भावनगर महानगरपालिका के आयुक्त रोजाना के कामकाज को संभालेंगे। हालांकि, इस दौरान वह कोई नीति विषयक निर्णय नहीं ले सकेंगे। इन ६ महानगरों में सामान्य चुनाव के पूरा होने के बाद और नए निर्वाचित पक्ष की पहली बैठक मिलने तक संबंधित मनपा आयुक्तरोजाना के कार्य संभालेंगे। महानगरों में रोजाना के जनहित के कार्य और व्यवस्था को कायम रखने और नागरिकों को असुविधा न हो उस उद्देश्य से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह निर्णय किया है।

शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर मांडवी के पीएसआई सस्पैंड

क्रांति समय संवाददाता

सूरत राज्य के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सूरत जिले में मांडवी पुलिस थाने के पीएसआई आईएम झाला को सस्पैंड कर दिया।

दरअसल सूरत ग्रामीण क्षेत्र के मांडवी पुलिस थानान्तर्गत पूना गांव में राज्य के स्टेट मोनिटरींग सेल छापेमारी की थी। इस छापेमारी में करीब रु ४६.०३ लाख कीमत की शराब पकड़ी गई थी। अपने क्षेत्र में शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पीएसआई आईएम झाला को पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने सस्पैंड कर दिया। राज्य में शराब तस्करी और जुए की गैरकानूनी गतिविधियों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस विभाग को यही संदेश देने के मकसद से आशीष भाटिया ने मांडवी के पीएसआई आईएम झाला को सस्पैंड किया है।

नए संसदभवन के भूमिपूजन कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सहभागी हुए मुख्यमंत्री

क्रांति समय संवाददाता

अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नए संसदभवन का भूमिपूजन किया। भूमिपूजन के इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गांधीनगर से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सहभागी हुए। गुरुवार को हुए भूमिपूजन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथसिंह समेत अन्य केन्द्री मंत्री, अधिकारी और विभिन्न कई महानुभाव

राज्य की ५१ नगरपालिकाओं के प्रशासकों को रोजाना के कार्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन का आदेश

क्रांति समय संवाददाता

अहमदाबाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य की ५१ ऐसी नगरपालिकाएं जिनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, वहां आम चुनाव का आयोजन होने तक संबंधित नगरपालिका के प्रशासक के रूप में कार्यरत चीफ ऑफिसर को उनकी नगरपालिका में रोजाना के कामकाज व कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के आदेश दिए हैं। नगरपालिका के प्रशासक इस अवधि के दौरान कोई नीति विषयक निर्णय नहीं ले पाएंगे। रूपाणी ने यह निर्णय इस मकसद से किया है कि संबंधित नगरों में रोजाना के जनहित के कार्य और व्यवस्था कायम रहे तथा नागरिकों को कोई असुविधा न हो।

राज्य की जिन ५१ नगरपालिकाओं में चीफ ऑफिसर को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें 'अ' श्रेणी की १६ नगरपालिका, 'ब' श्रेणी की २३ और 'क' श्रेणी की १२ सहित कुल ५१ नगरपालिकाओं का समावेश होता है। इसके अंतर्गत अहमदाबाद जिले की धोलका और वीरमगाम नगरपालिका, खेड़ा जिले की नड़ियाद और कपड़वंज नगरपालिका, सुरेन्द्रनगर जिले की ध्रांगध्रा और लींबड़ी नगरपालिका, बोटाद जिले की बोटाद नगरपालिका, पाटण जिले की पाटण और सिद्धपुर नगरपालिका, बनासकांठा जिले की पालनपुर और डीसा नगरपालिका, महेसाणा जिले की महेसाणा, कड़ी, उंझा और विसनगर नगरपालिका, साबरकांठा जिले की हिम्मतनगर नगरपालिका, अरवल्ली जिले की मोडासा नगरपालिका, गांधीनगर जिले की कलोल और दहेगाम नगरपालिका, पंचमहाल जिले की गोधरा नगरपालिका,

दाहोद जिले की दाहोद नगरपालिका, वडोदरा जिले की डभोई और पादरा नगरपालिका, आणंद जिले की आणंद, बोरसद, खंभात, पेटलाद और उमरेठ नगरपालिका,

तापी जिले की व्यारा नगरपालिका, नर्मदा जिले की राजपीपला नगरपालिका, भरूच जिले की भरूच, अंकलेश्वर और जंबुसर नगरपालिका, सूरत जिले की बारडोली और कडोदरा नगरपालिका, कच्छ जिले की गांधीधाम, भुज, अंजार और मांडवी नगरपालिका, देवभूमि द्वारका जिले की खंभालिया नगरपालिका, मोरबी जिले की मोरबी और वांकानेर नगरपालिका,

राजकोट जिले की गोंडल नगरपालिका, अमरेली जिले की अमरेली, सावरकुंडला और बगसरा नगरपालिका,

गिर सोमनाथ जिले की वेरावल-पाटण, ऊना नगरपालिका, जूनागढ़ जिले की केशोद नगरपालिका तथा भावनगर जिले की महुवा और पालीताणा नगरपालिका शामिल है।

पिलर से टकराई स्कोर्पियो कार, ३ युवकों की मौत, ३ गंभीर

क्रांति समय संवाददाता

साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर-शामलाजी हाईवे पर बुधवार की देर रात तेज रफ्तार स्कोर्पियो कार एक सड़क किनारे पिलर से टकरा गई ।

इस हादसे में स्कोर्पियो में

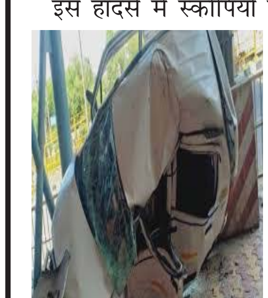

सवार तीन युवकों की मौत हो गई और तीन युवक घायल हो गए। घायलों को हिम्मतनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है । जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के अमराईवाडी क्षेत्र के ६ युवक स्कोर्पियो कार में साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर-शामलाजी हाईवे से गुजर रहे थे। उस वक्त गांभोई के निकट कार सड़क किनारे पिलर से टकरा गई। पिलर से टकराने के बाद कार पलटी खा गई, इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। जबकि ३ लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद यातायात ठप हो गया। घटनास्थल पर पहुंची गांभोई पुलिस ने क्रेइन की मदद से स्कोर्पियो कार को सड़क से हटाया और यातायात बहाल किया।

पुलिस ने घायलों को हिम्मत के अस्पताल रवाना किया

प.रे. महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा ने वलसाड में सराहनीय कार्य के लिए कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित

क्रांति समय संवाददाता

अहमदाबाद,वर्तमान में जारी कोविड-१९ महामारी के कारण हमारे राष्ट्र सहित पूरा विश्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पूरे देश में २२ मार्च, २०२० से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पश्चात् यात्री सेवाएँ बंद हो गईं थीं, जबकि फ्रेट एवं गुड्स ट्रेन सेवाएं अत्यावश्यक वस्तुओं के देश भर में परिवहन के लिए जारी हैं। इन सेवाओं के अलावा पश्चिम रेलवे पर नियमित एवं रूटीन अनुरक्षण के साथ-साथ विकास एवं ऑग्मेंटेशन कार्य भी जारी रहे। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग भी महामारी से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता एवं उपचार उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से आगे आया। पश्चिम रेलवे अपने मजबूत कार्य बल के साथ सहायता एवं सेवा प्रदान करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर लगातार मजबूती से डटी रही है। इन कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किये बिना बहादुरी एवं निस्वार्थ भाव से अपनी ड्यूटी निभाई। वलसाड क्षेत्र के विभिन्न विभागों के रेल कर्मियों द्वारा किये गये समर्पित एवं सराहनीय कार्यों को देखते हुए पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती तनुजा कंसल ने वलसाड में आयोजित एक समारोह में इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्रीमती तनुजा कंसल ने कोरोना योद्धाओं के बेहतरीन प्रयासों की सराहना की और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में कार्य के प्रति उनके साहस और समर्पण भावना के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती तनुजा कंसल ने विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले १० ऐसे रेल कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के सम्मान में प्रशंसा पत्र के साथ २००० रु के नकद पुरस्कार से सम्मानित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। इन १० रेलकर्मियों मे से छः कर्मी चिकित्सा विभाग, दो कर्मी परिचालन विभाग (नियंत्रक के रूप में कार्यरत), एक कर्मी रेल सुरक्षा बल से तथा अन्य एक कर्मी इलेक्ट्रिक लोको शेड वलसाड से है। इस अवसर पर सभी को सम्बोधित करते हुए श्रीमती कंसल ने चिकित्सा विभाग के मानवीय प्रयासों की सराहना की, जिन्होने संक्रमित मरीजों का पूरी सावधानी से

इलाज करने के साथ ही उन्हें मनोवैज्ञानिक सम्बल प्रदान करते हुए सकारात्मक वातावरण में उनके शीघ्र स्वास्थ लाभ बनाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये। इसी प्रकार उन्होंने चिकित्सा कर्मियों द्वारा कोविड-१९ महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए उनके विशेष प्रयासों एवं सावधानियों की भी प्रशंसा की। इन कर्मियों ने इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए ' क्वारंटाइन सेंटर एवं होम आइसोलेशन में रहे रहे रेल कर्मचारियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तथा स्टेशनों पर यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग का भी प्रबंध किया। श्रीमती कंसल ने समस्त फ्रन्टलाइन योद्धाओं की भरभूर प्रशंसा की। साथ ही उन कर्मियों की भी सराहना की, जिन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया और यात्रियों, पार्सलों व सामानों की स्क्रीनिंग की तथा जिन्होंने मरम्मत, अनुरक्षण एवं अपग्रेडेशन का कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन कर्मियों की भी तारीफ की, जिन्होंने भूखों एवं वंचितों में भोजन का वितरण किया। इसके साथ-साथ ही सेनिटाइजर, पी पी ई किट व सैनिटाइजिंग मशीन आदि को तैयार करने वाले कर्मियों की भी प्रशंसा की गई, क्योंकि सभी कर्मियों ने अपनी ड्यूटी पूरे लगन एवं समर्पण भाव से की। उन्होंने उन रेल कर्मियों एवं उनके परिवारजनों की भी सराहना की, जिन्होंने स्वेच्छा से घरेलू मास्क तैयार करने में रुचि ली। ठाकुर ने बताया कि स्मृति और प्रशंसा चिन्ह के रूप में श्रीमती तनुजा कंसल ने पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संस्था की ओर से वलसाड रेलवे अस्पताल को एक पी ए साउंड सिस्टम दान किया। इस पी ए सिस्टम का उपयोग मरीजों के लिए आनंद दायक संगीत सुनाने के लिए तथा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बंधी सूचनाओं को प्रदान करने के लिए किया जायेगा। इस अवसर पर सभी को सम्बोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कर्मचारियों और उनके परिजनों में कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न मानसिक तनाव के बारे में बताया गया और उसे दूर करने के लिए विभिन्न उपायों का डेमोंस्ट्रेशन दिया गया। वलसाड के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती तनुजा कंसल के प्रति अपना कृतज्ञता प्रकट की गई।

उन्होंने यह आश्वासन दिया कि कोविड-१९ के विरुद्ध लड़ाई में सामना करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे।

ठंड के बीच राज्य के कई जिलों में रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हुई

क्रांति समय संवाददाता

अहमदाबाद मौसम विभाग की रविवार तक राज्य में बारिश होने की संभावना के बीच आज कई जिलों में रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगामी रविवार तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में ठंड कम होने की संभावना है। अरब सागर में चक्रवात के असर से बारिश हो सकती है। हांलाकि चक्रवात का असर गुजरात में न हो और उसके समुद्र में समाने या

के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग की संभावना के बीच आज दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों में बारिश हुई। दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, तापी और सौराष्ट्र के अमरेली में बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक १२ दिसंबर तक दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और मध्य गुजरात के फिर ओमान की ओर रुख करने की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में आज यानी गुरुवार की रात से मौसम के बदलने और आसमान के बादलों से घिरे रहने की संभावना है। १३ दिसंबर तक राज्य में छुटपुट बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात के सूरत, भरूच, नवसारी, वलसाड के साथ ही सौराष्ट्र और मध्य गुजरात में भी बारिश की संभावना है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

जिम में अधिक एक्सारसाइज से युवक की मौत, आप रखें ध्यान

जींद। हुडा ग्राउंड स्थित गोल्ड जिम में ट्रेनर द्वारा अधिक एक्सरसाइज करवाने से एक युवक की मौत हो गई। स्वजनों ने जिम संचालक व ट्रेनर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पोस्टमार्टम चिकित्सकों के बोर्ड से करवाया है। अर्बन एस्टेट निवासी सरोज ने सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका 18 वर्षीय बेटा अभिषेक ने करीब दस दिन पहले ही हुडा ग्राउंड स्थित गोल्ड जिम में जाना शुरू किया था। सोमवार शाम को भी जिम में गया था, जबकि देर शाम को वह घर पहुंचा तो आते ही बैड पर गिर गया। जब उसने अभिषेक से पूछा तो उसने बताया कि जिम संचालक व ट्रेनर उस पर अधिक एक्सरसाइज करने का दबाव डालते हैं। सोमवार शाम को भी उससे ज्यादा एक्सरसाइज करवा दी। एक्सरसाइज करते समय ही उसका घबराहट हो गई। इसके बावजूद भी उससे एक्सरसाइज करवाते रहे। वह अपनी मां से बात करते हुए बेसुध हो गया। तबीयत बिगड़ती देखकर स्वजनों ने उसे तुरंत ही निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां पर चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालात देखते हुए रेफर कर दिया। बाद में जब उसे नागरिक अस्पताल में लेकर आए तो उसकी मौत हो चुकी थी। अभिषेक की मां सरोज ने आरोप लगाया कि उसके बेटे की मौत जिम संचालक नितीश बूरा व ट्रेनर नवदीप ईक्कस की लापरवाही के चलते हुई है। पुलिस ने जिम संचालक व ट्रेनर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ट्रेडमिल पर करवाई अधिक रनिंग

स्वजनों ने बताया कि अभिषेक को जिम ज्वाइन किए हुए केवल दस दिन हुए थे, लेकिन ट्रेनर उससे अधिक एक्सरसाइज करवाता था। अभिषेक को ट्रेडमिल पर रनिंग करवाई थी। जब अभिषेक थक गया तो उसके बावजूद भी ट्रेनर ने ट्रेड मिल पर रनिंग जारी रखने के लिए कहा। जब उससे नीचे उतारा तो उसका दिल मचलने लगा था। इसके बाद वह घर लौटा तो वह बेसुध हो गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी हरिओम ने बताया कि जिम संचालक व ट्रेनर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जिम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा जाएगा। युवक की मौत का कारण जानने के लिए चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है।

कोरोना से अधेड़ की मौत, 37 मरीज हुए स्वस्थ, 50 संक्रमित

अंबाला शहर। जिले में कोरोना के 50 केस संक्रमित मिले। बुधवार को 37 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर लौट गए। कोविड केस डबलिग दर भी 175 दिन तक पहुंच गई। एक अधेड़ की कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आने से मौत हो गई है। हालांकि मरीज दिल की बीमारी एवं शुगर रोग से ग्रस्त था। कोरोना के संक्रमण के आने से अब तक पाजिटिव मरीजों की संख्या 10850 हो गई है। इसी तरह 37 मरीज डिस्चार्ज हुए जिसके बाद डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 10252 हो गई है। अभी कुल एक्टिव मरीज 464 हैं। इलाज की दर अब 94.49 फीसदी हो गई है। अब तक 134 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, औसत मृत्यु दर 1.22 फीसदी है। कोरोना के संक्रमण से 60 वर्षीय पुरूष की मृत्यु हुई, जो छावनी का रहने वाला था। मरीज दिल की बीमारी एवं शुगर की समस्या थी। यह मरीज बाई पेप सपोर्ट पर था।

अंबाला शहर में आए सबसे अधिक मरीज

अंबाला शहर क्षेत्र में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मरीज आए हैं। 24 मरीज अंबाला शहर, 5 मरीज छावनी, 8 मरीज शहजादपुर, 5 मरीज मुलाना, 1 मरीज बराड़ा, 1 मरीज नारायणगढ़ और 6 मरीज चौडमस्तपुर से हैं। आए मरीजों में से 7 खानपुर राजपुताना शहजादपुर, 1 पंजलासा शहजादपुर, 1 न्यू मिलाप नगर शहर, 1 वशिष्ट नगर छावनी, 1 साहा, 1 शालीमार बाग, 2 सेक्टर दस, 3 सेक्टर 9, 1 जैन नगर, 1 हेमकुंड नगर, 1 अशोक नगर, 1 जग्गी कालोनी, 1 शास्त्री नगर, 3 जंडली, 1 कौलां, 1 विकास विहार, 1 रवि कालोनी, 1 रामनगर, 1 दो खंभा चौक, 1 नदी मुहल्ला, 1 हाउसिग बोर्ड छावनी, 1 राम नगर शहर, 1 सोनिया कालोनी, 1 बलदेव नगर, 1 सेक्टर 8, 1 अशोक नगर छावनी व 2 काजीवाड़ा समेत अन्य जगहों से संबंध रखते हैं।

आनलाइन एप से 56 मरीज अस्पताल में शिफ्ट

आनलाइन एप के जरिए 56 मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 1598 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। आइएलआइ के लक्षण वाले 128 मरीज मिले, जिनके सैंपल ले लिए गए हैं। दस मोबाइल टीमों ने अलग-अलग स्थानों में जाकर 627 व्यक्तियों का चेकअप किया गया। कुल लिए गए सैंपलों की संख्या 158333 हो गई है। इसमें से 120798 सैंपल आरटीपीसीआर से तथा 37535 सैंपल एंटीजन टेस्टिग किट से किए गए हैं। प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 140366 सैंपल लिए हैं।

अंबाला डिपो से चलीं 150 बसें, यात्रियों को राहत

अंबाला शहर। भारत बंद के असर से रोडवेज विभाग को करीब 12 लाख रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। इससे पूर्व डिपो को लॉकडाउन के दिनों में नुकसान हुआ था। बुधवार को डिपो की 150 बसें अलग-अलग मार्गो पर चलीं। ऐसे में यात्रियों को काफी राहत मिली है। डिपो की तरफ से रूटीन की तरह बसों को चलाया गया। सबसे ज्यादा आसानी उन यात्रियों को हुई जो लंबी दूरी पर जाने वाले थे। जबकि मंगलवार को भारत बंद के दिन यात्रियों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी।

डिपो के ये मार्ग कमाई का साधन

बता दें कोरोना महामारी से पहले दिल्ली, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड व यूपी में अंबाला रोडवेज डिपो की 68 बसों की सर्विस थी। डिपो से जम्मू-कटरा, पंजाब में अमृतसर, हिमाचल में रामपुर, उत्तराखंड में हरिद्वार व देहरादून तक बसों की अंतिम सर्विस थी। यह मार्ग डिपो की कमाई का साधन रहे। लेकिन कोरोना काल के दौरान इन्हें बंद कर दिया गया था। दिल्ली को छोड़ कर अब यह बसें इन लंबे मार्गो पर जा रही है।

सिंघु बॉर्डर तक ही जाएंगी बसें

रोडवेज की सभी बसें ऑन रूट है लेकिन दिल्ली की तरफ जाने वाली बसें आइएसबीटी की बजाय किसान सिघु बॉर्डर तक ही जाएंगी। बता दें डिपो की तरफ से 25 बसें दिल्ली जाती थी जो अब सिघु बॉर्डर तक ही जा रही है। यात्रियों को परेशानी हो रही है, उन्हें दिल्ली जाने के लिए बॉर्डर से अन्य व्हीकल को पकड़ना पड़ रहा है। ऐसे में उनका समय और परेशानी दोनों साथ-साथ झेलनी पड़ रही है। ट्रैफिक इंचार्ज रामफल का कहना है कि रोडवेज विभाग का प्रयास रहता है जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। बुधवार को सभी बसें रूट पर भेजी गई। दिल्ली मार्ग प किसान आंदोलन तक बसें सिघु बॉर्डर तक ही जाएंगी। हमने ग्रामीण रूटों को भी चालू कर दिया है इससे डिपो की रिसीट भी बढ़ी है।

कृषि कानूनों पर शरद पवार के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा कठघरे में

चंडीगढ़। केंद्र सरकार के तीन कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के बाद अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा घिरते नजर आ रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री स. मनमोहन सिंह की सरकार में हुड्डा मुख्यमंत्रियों की उस समिति के अध्यक्ष थे, जिसने 15 दिसंबर 2010 को केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कृषि कानूनों में सुधार की जरूरत बताते हुए उन्हें तत्काल लागू करने की बात कही थी।

हुड्डा के नेतृत्व वाले मुख्यमंत्रियों के समूह ने दस साल पहले की थी मंडी कानून में बदलाव की सिफारिश

भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली मुख्यमंत्रियों की इस समिति ने किसानों को फसल बेचने में होने वाली दिक्कतों का जिक्र करते हुए मंडी कानून में बदलाव का सुझाव दिया था। हुड्डा समिति ने केंद्र की मनमोहन सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बाजार ऐसे होने चाहिए, जहां किसान अपनी फसल को सीधे और आसानी से ग्राहकों तक बेच सकें। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को इन तीन कृषि कानूनों में अपनी फसल कहीं भी खुले बाजार में बेचने की आजादी दी है। अब वह इन कृषि कानूनों का खुलकर विरोध कर रहे हैं।

सीएम मनोहर ने उठाए हुड्डा के बदले स्टैंड पर सवाल, हुड्डा बोल- हमने अपनी सरकार में किए बड़े बदलाव

इतना ही नहीं, हुड्डा का नजरिया भी अब बदल गया है। विधानसभा में उन्होंने खुलकर कहा था कि केंद्र सरकार भले ही तीनों कृषि कानून लागू रखे, लेकिन उसे एमएसपरी (फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी देने वाला चौथा कानून बना देना चाहिए। इससे किसान व विपक्ष मान जाएंगे। हुड्डा ने दो दिन पहले दिल्ली में जो प्रेस कान्फ्रेंस की है, उसमें वह इन तीनों कृषि कानूनों को रद करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लग रहा कि पूरा आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुड्डा के इस स्टैंड पर सवाल उठाए हैं।

किसान समझें मोदी उनका अहित क्यों होने देंगे- मनोहरलाल

किसानों को यह समझने की जरूरत है कि उनकी आय डबल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के अहित कैसे होने देंगे। भाजपा हमेशा से ही किसानों के हितों की पक्षधर रही है। जिन कुछ मुद्दों पर किसानों को असमंजस है, उन्हें सरकार चर्चा के बाद दूर कर रही है। अच्छी बात यह है कि इस आंदोलन में हरियाणा के किसान नहीं हैं, क्योंकि वह जान रहे हैं कि इन कानूनों का उन्हें फायदा है और उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। यह आंदोलन राजनीतिक बन गया है। उन्हें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का टूल बनने से बचना होगा।

प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा दे रही भाजपा सरकार- हुड्डा

किसानों को एमएसपी का संरक्षण ज़रूरी है। सरकारी मंडियों का विस्तार होने से ऐसा होगा। मौजूदा सरकार प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा दे रही है। कांट्रेक्ट फार्मिंग क़ानून किसानों के हित में नहीं है। इसमें न एमएसपी का जक्रि है और न कोर्ट जाने का अधिकार। हमारी सरकार ने अगस्त 2007 में नियम बनाया था, जिसमें था कि एमएसपी से कम पर कोई कांट्रेक्ट नहीं होगा। मेरे नेतृत्व वाले मुख्यमंत्रियों के समूह ने किसानों के सशक्तीकरण के लिए क्रांतिकारी सिफारिशें की थी। फसली ऋण का ब्याज 12 प्रतिशत से कम कर चार प्रतिशत किया। हरियाणा में कांग्रेस ने इसे शून्य कर दिया। यूपीए सरकार में एमएसपी में सालाना 13 से 14 प्रतिशत बढ़ोतरी होती थी, जबकि भाजपा में यह चार से पांच प्रतिशत है।

– **भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम, हरियाणा।**

झज्जर में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत, सात लोग घायल, शादी में हो गया मातम

झज्जर/हिसार। झज्जर जिले के विभिन्न एरिया में सोमवार-मंगलवार मध्यरात्रि हुए तीन सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद तीन परिवारों में मातम छाया हुआ है। वहीं 7 लोग घायल हो गए। जिनका उपचार चल रहा है। इनमें से दो हादसे उस समय हुए जब रात को युवक गाड़ियों में बैठकर बरात में जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतकों व घायलों के स्वजन जिला अस्पताल में पहुंचे। जहां पर पुलिस ने बयान दर्ज करके कार्रवाई करते हुए शवों के पोस्टमार्टम करवाए। हादसा नंबर एक - कोसली रोड पर शहर के नजदीक निर्माणाधीन पुल के पास उस समय हादसा हुआ जब गांव चांदपुर निवासी दिनेश, गांव जौंधी निवासी ऋषि, प्रदीप व चांद सिंह गाड़ी में सवार होकर गांव रईया से झज्जर आ रहे थे। इसी बीच कार अनियंत्रित हो गई और कैंटर से जा टकराई। इस हादसे में घायल चारों को उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने 25 वर्षीय दिनेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं चांद सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआइ रेफर कर दिया। हादसा नंबर दो - गांव गुढ़ा के नजदीक ओवर ब्रिज के समीप गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार होकर रेवाड़ी जिला के कोसली निवासी 24 वर्षीय हर्ष, भिवानी जिला के गांव मित्ताथल निवासी सुखवेंद्र, गुरुग्राम निवासी सैंडी, विपिन व संदीप सभी अपने साथी की शादी में गांव डीघल गए हुए थे। रात को गांव डीघल से झज्जर आते समय रास्ते में गुढ़ा ओवरब्रिज के समीप कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में हर्ष की मौत हो गई। वहीं अन्य को चोटें आई है। जांच अधिकारी एसआइ कृष्ण कुमार ने घायल सुखवेंद्र के बयान पर कार चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गांव दुल्हेड़ा के पास सोमवार-मंगलवार मध्य रात्रि एक अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। प्राथमिक दृष्टि से मृतक की उम्र करीब 35-40 वर्ष लग रही है और मजदूरी करने वाला प्रतीत हो रहा है। जांच अधिकारी हरीश ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने आसपास के चौकी व थानों में इसकी सूचना दे दी है। वहीं आसपास में भी पूछताछ की जा रही है।

कालेज परिसर में पेड़ कटाई का विवाद थाने पहुंचा, एक पक्ष नदारद

किसी कारण से दूसरा पक्ष थाने में नहीं आया है। अब 11 दिसंबर को दोनों पक्षों को बुलाया गया है। तब तक लकड़ी की कटाई नहीं होगी।

मुलाना। महाराणा प्रताप नेशनल कॉलेज मुलाना में लकड़ी कटाई के विवाद में बुधवार सुबह मुलाना थाना में ग्रामीण अपने कागजात लेकर पहुंचें, लेकिन कॉलेज प्रबंधन थाना में नहीं पहुंचा। इस दौरान थाने पहुंचे एक पक्ष ने संबधित कागजात पुलिस को दिखाए। इसके बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष की करीब दो घंटे तक प्रतीक्षा की, ताकि वह थाना में आकर अपना पक्ष बता सकें। इसके बाद ग्रामीण भी थाना से चले गए। बता दें कि मंगलवार को कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई शुरू की थी। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए रूकवा दिया। मौके पर पुलिस भी पंहुची। बुधवार सुबह दोनों पक्षों को मुलाना थाना बुलाया था। ग्रामीणों का आरोप था कि लगभग 55 एकड़ भूमि पर लकड़ी खड़ी है। लकड़ी की अनुमानित कीमत लगभग दो से ढाई करोड़ है। कॉलेज प्रबंधन लकड़ी को काफी कम दामों पर बेच रकम हड़पना चाहता है। वहीं कॉलेज प्रबंधन व समिति के अनुसार लकड़ी कटाई का काम नियमों के तहत किया गया है। उन्होंने ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया। दोनों पक्षों को 11 को थाने में बुलाया मुलाना थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मुलाना के ग्रामीण थाने में आये थे। किसी कारण से दूसरा पक्ष थाने में नहीं आया है। अब 11 दिसंबर को दोनों पक्षों को बुलाया गया है। तब तक लकड़ी की कटाई नहीं होगी।

किसान आंदोलन : हरियाणा में बड़े सहकारी संघों का जन्मदाता बनेगा कांट्रैक्ट खेती कानून

नई दिल्ली। हरियाणा देश में पहला ऐसा राज्य होगा, जिसके किसान के खेत में होने वाली हर प्रकार की पैदावार को व्यवस्थित ढंग से खरीदा जाएगा। राज्य में कृषि कानूनों में कांट्रैक्ट खेती के प्रावधान से बड़े सहकारी संघ बनेंगे। इसके साथ ही तीन कृषि सुधार कानून लागू होने के बाद हरियाणा मल्टीपर्पज कोआपरेटिव फेडरेशन (हमकोफेड) के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिला में 600 की औसत से करीब 14 हजार सहकारी सममियां गठित होंगी।

तीन कृषि सुधार कानून बनने के बाद प्रशस्त हुआ हमकोफेड का प्रारूप

इनके माध्यम से न सिर्फ किसान के खेत से पैदावार खरीदी जाएगी बल्कि समितियां अपने बिक्री केंद्रों (आउटलेट) के माध्यम से आम उपभोक्ता तक पहुंचाएंगी। हमकोफेड के चेयरमैन हुकमचंद भाटी बताते हैं कि तीन कृषि सुधार कानूनों में खेती में अनुबंध के कानून से यह संभव पाएगा। किसान मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा अध्यादेश-2020 के तहत बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि सहकारी समितियां भी किसान से उसकी उपज का भाव और खरीद तय कर सकेंगी। भाटी के अनुसार, अभी तक के आंकड़े हैं कि किसान की 40 फीसद सब्जियां व्यर्थ हो जाती हैं। इनकी व्यवस्थित बिक्री का प्रावधान नहीं है। जब न्यूनतम 200 सदस्यों की एक सहकारी समिति अपने आसपास के किसानों से उसकी सब्जियों की फसल खरीदकर उसे अपने ही बिक्री केंद्रों पर बेचेगी तो निश्चित तौर पर व्यर्थ होने वाली सब्जियों की मात्रा घट जाएगी। हमकोफैड पहले चरण में किसानों को फल सब्जियां बोने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही किसान की फसल उसके खेत से थोक मंडी के भाव पर लेकर अपने बिक्री केंद्रों पर बेचेगा। इसकी शुरूआत फरीदाबाद जिला में 11 दिसंबर से होगी। इसके बाद किसान को आधुनिक तकनीक व बीज आदि उपलब्ध कराने की सहूलियत भी हमकोफैड करेगा। यदि सहकारी समितियों के बिक्री केंद्रों पर माल की बिक्री नहीं होती तो उनसे संबंधित अन्य खाद्य पदार्थ बनाने वाले वाले लघु उद्योगों से संपर्क किया जाएगा। ये खाद्य पदार्थ भी सहकारी समितियों के बिक्री केंद्रों पर बेचे जाएंगे। भाटी का कहना है कि कांट्रैक्ट खेती कानून पर भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी तक किसान का बेटा खेती के प्रति इसलिए आकर्षित नहीं होता था, क्योंकि उसे खेती में निश्चित आय का वजूद नहीं दिखाई देता। मगर जब खेत में बुवाई के दौरान ही उसे यह पता चल जाएगा कि उसकी फसल से उसे कितना पैसा मिलेगा तो उसका खेती के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।

यही आकर्षण किसान की आमदनी दोगुना करने का आधार बनेगा। कृषि लाभकारी कैसे हो। इसकी पहल सरकार के साथ किसान को भी करनी पड़ेगी। किसान को मुखर, दूरदृष्टि वाला व आधुनिकता के साथ कृषि में वैज्ञानिक तरीके अपनाकर सरकार द्वारा दी गई कृषि सुविधाओं का लाभ लेकर समय के अनुकूल चाल ढाल को बदलना भी जरूरी है। संपर्कों के साथ हमकोफैड किसानों में बदलाव का आधार भी रखेगा।

नप दुकानों को मालिकाना हक देने की योजना ठंड बस्ते में

अंबाला। अंबाला कैंट नगर परिषद (नप) के सदर क्षेत्र में आनी वाली दुकानों को उनके मालिकों को देने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। करीब एक साल पहले नप ने इसी को लेकर कार्रवाई की थी, लेकिन मामला दुकानों की पैमाइश से आगे नहीं बढ़ पाया है। सालों से नप की दुकानों में बैठे इन दुकानदारों को उम्मीद थी कि दुकानें उनके नाम हो जाएंगी, लेकिन मामला सिरे ही नहीं चढ़ पाया है। अंबाला सदर क्षेत्र में नप की अपनी करीब 970 दुकानें हैं, जो किराये पर हैं। प्रदेश सरकार के पिछले कार्यकाल में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से नगर परिषद की दुकानें, जो किराये पर हैं, उनके मालिकों दुकानों का मालिकाना हक देने की योजना पर काम शुरू किया था।

बारिश के आसार से किसान चिंतित

अंबाला शहर। मौसम के बदलते रूख को देख कर किसान परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गेहूं फसल की सिचाई की थी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। जिसे लेकर किसान चितित हैं। बारिश होने पर गेहूं की फसल पीली भी पड़ सकती है। खेतों से पानी की निकासी न हुई तो गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग की मानें तो 11 और 12 दिसंबर को बारिश होने की संभावना है। गेहूं की फसल को पानी की जरूरत नहीं है। बलाना के किसान इंद्रजीत सिंह ने बताया कि गेहूं की पूरी फसल को महज दो या तीन बार ही पानी दिया जाता है। इससे अधिक कभी भी गेहूं की फसल की सिचाई नहीं की जाती है।

कैथल में एक भाई की मौत, दूसरा चार दिन से लापता, घर से लेकर सड़क तक मची हाहाकार

कैथल। कैथल शहर की शिव कालोनी से दो सगे भाई गांव कुतुबपुर में दिहाड़ी-मजदूरी करने के लिए गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस थाने से परिवार के लोगों के पास एक फोन आया कि एक युवक को चोटें लगी हैं। इसका इलाज करवा लो। युवक को ज्यादा चोटें थीं। उसने पीजीआइ चंडीगढ़ में पहुंचते ही दम तोड़ दिया। बंटी का चार दिन से कोई सुराग नहीं लगा है। स्वजनों का आरोप है कि गांव कुतुबपुर के एक मछली पालन करने वाले ठेकेदार ने दोनों भाइयों पर मछली चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की थी और थाना सदर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने भी उसे पीटा और इलाज कराने की बजाय उन्हें सौंप दिया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वजनों ने शहर के बीचोंबीच पिहोवा चौक पर जाम लगा दिया। मौके पर एसडीएम डा.संजय कुमार और थाना सदर प्रभारी राजफूल ने पहुंचकर उन्हें बताया कि इस मामले में दो ठेकेदारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। डेढ़ घंटे तक स्वजनों ने पिहोवा चौक पर जाम लगाए रखा। अनिल की बहन ऊषा और बड़े भाई मनोज ने बताया कि 32 वर्षीय अनिल और 28 वर्षीय बंटी मजदूरी के लिए गांव कुतुबपुर में जाते थे। छह दिसंबर को मत्स्य पालन करने के वाले ठेकेदार गांव शेरुखेड़ी निवासी संजय और गांव शेरगढ़ निवासी विक्रम ने दोनों पर मछली चोरी का आरोप लगाते हुए उनको बुरी तरह से पीटा। अनिल को पुलिस थाने में सौंप दिया, लेकिन बंटी के बारे में अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। ऊषा और मनोज का कहना है कि बंटी उसी तालाब में मिलेगा। ठेकेदारों ने उसे भी मारपीट कर तालाब में फेंक दिया होगा। अनिल अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चे छोड़ गया है, जबकि बंटी के चार बच्चे हैं। अनिल की पत्नी मूर्ति और बंटी की पत्नी सुदेश का रो-रो कर बुरा हाल है। वे बार-बार बेसुध हो रही थीं। जाम लगाए स्वजनों और कालोनीवासियों का कहना है कि पुलिस ने भी अनिल को पीटा है, जिसकी वजह से उसे गहरी चोटें लगी। फिर उसका इलाज भी नहीं करवाया और आनन-फानन में परिवार को सौंप कर इलाज कराने को बोलकर पल्ला झाड़ लिया। तब तक उसकी हालत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसके चलते स्थानीय सिविल अस्पताल से उसे पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था, जहां जाकर उसकी मौत हो गई। इस मामले में स्वजनों की शिकायत पर गांव शेरुखेड़ी निवासी ठेकेदार संजय और शेरगढ़ के विक्रम के खिलाफ अनिल की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बंटी की तलाश की जा रही है। आरोपितों की जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अनिल से पुलिस थाने में मारपीट के आरोप गलत हैं।

– **राजफूल सिंह, एसएचओ थाना सदर।**

किसान आंदोलन : दूध-सब्जियों की सप्लाई चेन टूटी, दिल्ली के साथ हरियाणा-यूपी पर असर

चंडीगढ़। किसानों के आंदोलन और हजारों की संख्या में दिल्ली-हरियाणा बार्डर पर जमे रहने के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में दूध-सब्जियों की सप्लाई की चेन टूट गई है। इससे दूध और सब्जी उत्पादक किसान बेहद मुश्किल में हैं। इसका असर दिल्ली के साथ ही हरियाणा व उत्तर प्रदेशपर पड़ रहा है। इस तरह किसानों के दर्द को किसान ही नहीं समझ नहीं रहे हैं।

किसान ही नहीं समझ रहे किसानों का दर्द

हरियाणा की गिनती देश के सबसे ज्यादा अन्न उत्पादक राज्यों में तो होती ही है, दूध उत्पादक राज्यों की श्रेणी में भी हरियाणा आठवें स्थान पर है। फसल विविधिकरण अपनाते हुए हरियाणा के प्रगतिशील किसानों व किसान उत्पादक संगठनों का जोर सब्जी, फल, मसाले और फूलों का उत्पादन बढ़ाने पर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा होने के कारण हरियाणा का किसान दिल्ली के लोगों की दूध, फल, सब्जियों व फूलों की जरूरत को बरसों से पूरा कर रहा है। यह एक चेन बनी हुई है, जिसमें किसान व मजदूर से लेकर दिल्ली का हर वीआइपी व जरूरतमंद उपभोक्ता जुड़ा हुआ है, मगर किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से दिल्ली की चारों तरफ से घेराबंदी की गई है, उससे न तो हरियाणा के दूध व सब्जी उत्पादकों का माल दिल्ली जा रहा है और न ही दिल्ली के लोगों की दूध व सब्जियों की जरूरत पूरी हो पा रही है।

दिल्ली व एनसीआर हरियाणा के सब्जी व दूध उत्पादकों के लिए बड़ा बाजार मगर नहीं हो रही सप्लाई

ऐसी स्थिति सिर्फ हरियाणा की सीमा के प्रवेश द्वार बाधित होने से नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले किसानों व दूध उत्पादकों के साथ भी यही समस्या है। इसका सबसे बड़ा नुकसान सब्जी व दूध उत्पादक किसानों को रहा है, जिन्हें हर रोज अपने उत्पाद यानी दूध और सब्जियां या तो नष्ट करनी पड़ रही हैं या फिर सस्ते दामों पर अपने-अपने इलाकों में ही निकालनी पड़ रही है। सरल भाषा में हम यूं कह सकते हैं कि किसान हितों के नाम पर बार्डर पर जो किसान जमा हैं, वही अपने वास्तविक जरूरतमंद किसान की आय और प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं।

सीमाएं सील होने के कारण हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश की सब्जियां व दूध भी नहीं पहंच रहा दिल्ली

तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि इन किसानों व पशुपालकों के सामान की दिल्ली में सप्लाई नहीं होने के कारण उसे हरियाणा में सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है, लेकिन हरियाणा के लोगों को सस्ते दामों पर यह उपलब्ध नहीं हैं। किसान को गोभी दो से तीन रुपये किलो में निपटानी पड़ रही है, लेकिन मंडी व रेहड़ी पर यह रेट 20 से 40 रुपये किलो तक है। यही स्थिति दूध की है। दूध उत्पादक किसान घरों में सप्लाई करने वाले दूध की मात्रा बढ़ाकर लेने का अनुरोध अपने नियमित ग्राहकों से कर रहे हैं। इससे भी इतर, दिल्ली के लोगों को दूध व सब्जियों की किल्लत के चलते वहां महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ रहा है। आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के महासचिव नवीन गुप्ता का कहना है कि आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही प्रभावित है। यह नुकसान की बड़ी वजह है। हरियाणा में करीब 18 लाख किसान खेती के व्यवसाय से जुड़े हैं। यहां बागवानी फसलों की खेती अभी 4.52 लाख हेक्टेयर में की जाती है। कुल उत्पादन 25.1 लाख टन होता है। अगले 10 सालों में बागवानी का क्षेत्रफल बढ़ाकर नौ लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल उत्पादन 270 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है। ऐसा फसल विविधिकरण के चलते किया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली-एनसीआर में तकरीबन पांच करोड़ लोग रहते हैं। साल दर साल फल-फूल व सब्जियों की मांग बढ़ रही है। हरियाणा इसकी आपूर्ति करने वाला प्रमुख राज्य बना हुआ है, जो भविष्य में रफ्तार पकड़ सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टिकरी बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने पहुंचेंगे अभय चौटाला

सिरसा। इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक ली और उन्हें 8 दिसंबर को किसानों के समर्थन में भारत बंद को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभी को निर्देशित किया गया कि पार्टी की ओर से आग्रहपूर्वक बाजार व प्रतिष्ठान बंद करवाते हुए किसानों का सहयोग किया जाएगा। बैठक के दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भारत बंद में किसानों को पूर्ण समर्थन देने के साथ-साथ आगामी 9 दिसंबर को वे भावदीन टोल नाके से सुबह 9 बजे काफी संख्या में इनेलो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे और वहां पर किसानों से मिलेंगे और उन्हें पार्टी की ओर से पूरा समर्थन देंगे। इनेलो प्रधान महासचिव ने इस दौरान कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हठधर्मिता पर है और उसे ये हठ छोड़कर किसानों व देश के हित में बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेना चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी का पहले दिन से ही किसानों के पक्ष में स्टैंड था कि भाजपा सरकार की ओर से बनाए गए तीनों कृषि कानून पूरी तरह से किसान और कृषि के खिलाफ हैं और सरकार को इन्हें तुरंत वापिस लेना चाहिए। इनेलो नेता ने कहा कि इनेलो पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता इस आंदोलन को मजबूत करने और केंद्र की सरकार द्वारा थोपे गए तीनों काले कानूनों को खत्म करने के लिए कंधे से कंधा मिला कर इस लड़ाई को लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को सफल बनाने में कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो वे पीछे नहीं हटेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि देश के किसी भी किसान संगठन ने इन कृषि कानूनों की मांग नहीं की थी लेकिन केंद्र की सरकार ने कारपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए ये काले कृषि कानून बनाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तीनों काले कानूनों को खत्म करके किसानों को फसल की एमएसपी की गारंटी दे और जो भी एजेंसी किसान की फसल को एमएसपी से नीचे खरीदे उस पर आपराधिक मुकद्मा दर्ज कर सजा का प्रावधान करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार किसान को उसकी फसल का दाम मिले। इनेलो नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़कर किसान संगठनों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनकी बात को मानना चाहिए ताकि देश में कृषि और किसान सुरक्षित रह सकें। बैठक के दौरान इनेलो की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जसवीर सिंह जस्सा, इनेलो महिला विंग की जिलाध्यक्ष कृष्णा फौगाट, इनेलो के जिला प्रेस प्रवक्ता महावीर शर्मा, ऐलनाबाद हलका प्रधान अभय सिंह खोड, सिरसा के हलकाध्यक्ष गुरविंद्र सिंह, डॉ. विनोद गोदारा, विनोद दड़बी, धर्मवीर नैन, रामकुमार नैन व महेंद्र बाना सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे।

खेल निदेशालय को भेजा साइकिल प्रतियोगिता का प्रस्ताव

अंबाला। जिला खेल विभाग अंबाला में साइकिल प्रतियोगिता की तैयारी में लगा है। इसी को लेकर खेल विभाग ने प्रस्ताव बना कर मंजूरी के लिए निदेशालय भेजा है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद अंबाला में यह पहला मौका होगा जब इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन होगा। दूसरी ओर वार हीरोज स्टेडियम में ही बनने वाले जिमनास्टिक प्रैक्टिस रूम के एस्टीमेट का भी इंतजार किया जा रहा है। यह दोनों ही प्रपोजल खिलाड़ियों के लिहाज से अहम हैं। जिला खेल विभाग अंबाला में साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहता है। इसके लिए लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग वर्ग में यह प्रतियोगिता कराई जाएगी। खेल विभाग ने दोनों वर्गो में इनाम राशि भी तय की है। अंबाला में साइकलिंग कोच है, लेकिन जिला स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिता लंबे समय से नहीं हो पाई है। इसी कारण से विभाग ने भी तैयारी की है कि इस तरह की प्रतियोगिता हो। प्रस्ताव की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद इसका रूट भी तय किया जाएगा। विभाग इस प्रस्ताव की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर जिमनास्टिक के खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस रूम भी तैयार किया जाना है। इसका प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग को भेजा गया है। इसका बजट कितना होगा यह संबंधित विभाग इसकी रिपोर्ट बना कर खेल विभाग को सौंपेगा। इसके बाद यह मुख्यालय को भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा।

प्रस्ताव मंजूरी मिलने पर करेंगे तैयारी = सत्यन

इस बारे में जिला खेल विभाग एन सत्यन ने बताया कि साइकिल रैली के लिए मुख्यालय को प्रपोजल भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद आगामी तैयारी की जाएगी। इसके अलावा जिमनास्टिक खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस रूम का बजट तैयार किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी बी एंड आर एस्टीमेट बनाकर देगा, जिसे मुख्यालय भेजा जाएगा।

कच्चे माल की कीमत बढ़ने से मिक्सी उद्योग पर संकट

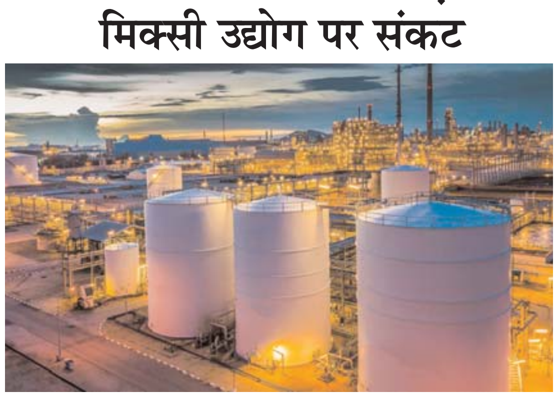

अंबाला शहर। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से मिक्सी उद्योग पर संकट खड़ा हो गया है। प्लास्टिक दाने, कॉपर और लोहे में उछाल आने से मिक्सी कारोबारियों के पास डिमांड में कमी आ गई है। नए आर्डर नहीं आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में बाहर से आने वाली मिक्सी पर रोक लग गई थी। इसके बाद जिला में मिक्सी कारोबार उबरने लगा था। क्योंकि यहां से मिक्सी की डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन अब कच्चे माल की कीमतों ने सिस्टम बिगाड़ दिया है। प्लास्टिक दाने के दामों में डेढ़ सौ फीसदी तेजी हो गई। जबकि पहले 160-165 रुपये एबीएस दाना था। इस दाने से बॉडी बनती है, परंतु अब दाना की कीमत 380 रुपये तक पहुंच गई है। मॉल्डिंग करने वाले बॉडी बनाने का कांट्रैक्ट लेते हैं, जो दाने से तैयार होती है। महंगा होने पर दाने की खरीद नहीं हो रही, क्योंकि इस भाव पर मिक्सी विक्रेता खरीद नहीं करते है। इसी तरह कॉपर भी लॉकडाउन के दौरान साढ़े 4 सौ से 500 तक भाव था, जो अब 690 रुपये हो गया है। लोहे में दामों में भी 20 फीसदी बढ़ोतरी हो गई है। पहले 48 रुपये की शीट मिलती थी। वहीं शीट अब 60 रुपये तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर 25 फीसदी तक दामों में बढ़ोतरी हो गई है। पहले जो चीज 400 रुपये में बिकती थी, वह अब 500 रुपये तक पहुंच गई। कैशियर मोहन लाल सैनी ने बताया कि अंबाला से मिक्सी की सप्लाई पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तक किया जाता है। अंबाला में 15 के करीब मिक्सी के मैन्युफैक्चर्स हैं। 15 के करीब यूनिट है।

पिछड़ रहा मिक्सी उद्योग = अजय

मिक्सी यूनियन के प्रधान अजय अग्रवाल ने बताया कि इस इंडस्ट्री की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस कारण मिक्सी उद्योग अंबाला में पिछड़ता जा रहा है। हरियाणा के मुकाबले बद्दी में बिजली सस्ती दरों पर मिल जाती है।

एचडीएफ को कप-प्लेट चुनाव चिह्न आवंटित

अंबाला शहर। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नगर निगम चुनावों में मेयर पद और पार्षद दोनों के निर्वाचन के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 48-48 अलग अलग फ्री सिंबल्स (खुले चुनाव चिह्नों) की सूची जारी की थी। इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और हरियाणा के दो क्षेत्रीय दलों के नाम और उनके आरक्षित चुनाव चिह्नों का भी उल्लेख है। फ्री सिंबल सूची में कप-प्लेट न होने बावजूद एचडीएफ को आवंटित कर दिया गया। इसे लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने पत्र लिखा है। बता दें हाल में चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट (एचडीएफ) राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड की गई है। एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया आज तक एचडीएफ के नाम, चुनाव चिह्न और झंडे पर कोई चुनाव नहीं लड़ा गया है। वर्ष अक्टूबर, 2019 में निर्मल सिंह ने शहर और उनकी पुत्री चित्रा सरवारा ने अंबाला कैंट विधानसभा हलके से आजाद प्रत्याशी के तौर पर विधायक का चुनाव लड़ा था और दोनों अपने-अपने हलके में 36-36 फीसद से अधिक वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दोनों को अपने अपने हलके में कप-प्लेट का ही चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था। इन दोनों का दर्जा निर्दलीय उम्मीदवार का ही था। इस प्रकार कप-प्लेट चुनाव चिह्न आवंटित करवाने का एचडीएफ का अधिकार नहीं बनता। चूंकि न तो मेयर पद और न पार्षद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 48-48 फ्री सिंबल्स की सूची में कप-प्लेट का चुनाव चिह्न है ही नहीं है। कानूनी तौर पर यह देखने लायक है कि क्या उपरोक्त एक दिसंबर की नोटिफिकेशन या 15 नवंबर 2018 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हरियाणा नगर निगम चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 2018 में उपर्युक्त एवं प्रासंगिक संशोधन किए बिना क्या एचडीएफ के उम्मीदवारों को दो नगर निगमों के चुनावों में सीधे तौर पर कप-प्लेट का चुनाव चिह्न आवंटित कर सकता है क्या।

आरोपित कर्मबीर बोला वारदात को अंजाम देने के लिए शैलेंद्र ने बुलाया था तीनों को

अंबाला शहर। प्रॉपर्टी विवाद का हवाला देकर खुद को चाकू मरवाने के लिए वकील शैलेंद्र मोहन ने तीनों रिश्तेदार आरोपित बसंत, श्रवण और कर्मबीर को अपने घर कैलाश नगर बुलाया था। यह खुलासा आरोपित वकील शैलेंद्र के मौसेर भाई कर्मबीर ने अब तक पूछताछ में खुलासा किया है। यह बयान पहले गिरफ्तार किए जा चुके बसंत और श्रवण दे चुके हैं। तीनों ने अब तक अपने यही बयान दर्ज करवाए हैं। उधर आरोपित कर्मबीर को कोर्ट में पेश किया गया जहां से पूछताछ के लिए एक दिन का पुलिस रिमांड मंजूर हुआ है, जबकि मास्टरमाइंड वकील शैलेंद्र घर से फरार चल रहा है।

मास्टर माइंड निकला वकील

20 नवंबर को खुद के चैंबर में चाकू से हमला करवाने के मामले में आरोपित वकील शैलेंद्र मोहन मास्टर माइंड निकला। यह पूरा प्लान शैलेंद्र ने 17 नवंबर को तीनों रिश्तेदार बसंत, श्रवण और कर्मबीर को अपने घर बुलाकर तैयार किया था। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपितों ने बताया कि इससे पहले उन्हें कुछ पता नहीं था। शैलेंद्र ने चैंबर में आकर कब और कितने बजे आना है यह सारा प्लान उन्हीं का था। उधर, जब आरोपित वकील शैलेंद्र मोहन को पहली बार आरोपित बसंत और श्रवण की गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो वह घर से फरार हो गया। पुलिस उसके घर कैलाश नगर में बार दबिश दे चुकी है, हर बार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा है। बता दें 20 नवंबर को शैलेंद्र मोहन ने पड़ोसी को प्रॉपर्टी विवाद में फंसाने के लिए खुद पर तीनों रिश्तेदारों से चाकू

बेटियों के लिए अनोखी मुहिम, बिन मां की बेटी की शादी में दे रहे 51 हजार रूपए का कन्यादान

भिवानी/ढिगावामंडी। समाजसेवी तो बहुत से देखे होंगे। मगर भिवानी जिले में एक ऐसे भी समाजसेवी हैं जो बेटियों के लिए समर्पित हैं। उन्होंने एक ऐसी अनोखी मुहिम छेड़ी है कि हर जगह उनके प्रयास की सराहना हो रही है। समाजसेवी एवं पूर्व जिला प्रमुख राजबीर फरटिया लोहारू हलके में चाहे किसी भी बेटी की शादी क्यों न हो। वे 5100 रुपये का कन्यादान देते हैं। वहीं अनाथ बेटी की शादी में एक लाख रुपये कन्यादान देते हैं। इसके अलावा बिन मां की बेटी की शादी में 51000 हजार रुपये देते हैं। पहले बिन मां की बेटी को वे 5100 रुपए कन्यादान ही देते थे मगर अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 51 हजार कर दिया है। उनका कहना है कि बेटी चाहे किसी की भी हो उनकी शादी में सहयोग करके उन्हें बेहद खुशी मिलती है। राजबीर फरटिया मंगलवार तक करीब 700 बेटियों की शादी में 5100-5100 रुपए व छह अनाथ बेटियों की शादी में एक -एक लाख रुपये का शगुन दे चुके हैं। राजबीर फरटिया ने मंगलवार को ढिगावा मंडी के गांव बड़दू धिरजा में एक शादी समारोह के दौरान नई घोषणा करते हुए कहा कि बिना मां की बेटी को अब 5100 रुपये नहीं बल्कि बढ़ाकर 51000 रुपये कन्यादान दिया जाएगा। पूर्व जिला प्रमुख का कन्यादान अभियान लगातार तेजी पकड़ रहा है, निमंत्रण ज्यादा मिलने शुरू हो गए तो उन्होंने अपने साथियों की एक टीम गठित कर दी है जो कन्या दान करने में उनका निरंतर सहयोग करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की मुहिम रंग ला रही है और बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग मिल रहा है। इस बात का असर इस कदर हो रहा है कि दो चार लोग इकट्ठे होते ही पूर्व जिला प्रमुख की कन्यादान अभियान की चर्चाएं शुरू कर देते हैं। राजबीर फरटिया ने बताया की हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक, महादान की श्रेणी में कन्यादान को रखा गया है। जो कि इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। वे देर रात्री तक हल्के की प्रत्येक बिटिया की शादी में पहुंच कर कन्यादान कर अपना आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने कहा रक्तदान और कन्यादान जैसा कोई दान नहीं है। लोगों को आगे आकर इस तरह की मुहिम में जुड़ना चाहिए।

गैर मान्यता व अस्थाई मान्यता को मिला एक साल का समय

अंबाला शहर। प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त और अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल संचालक लंबे समय से परेशान थे जिन्हें अब राहत मिली है। 7 दिसंबर को पत्र जारी करते हुए इन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2 लाख बच्चों को भी राहत मिली है। पत्र के जारी होने के बाद यह स्कूल भिवानी बोर्ड से संबद्धता कर पाएंगे। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। मालूम हो कि वर्ष 2007 से प्रदेश भर के 3200 स्कूलों को मान्यता देने का मामला लटका हुआ था, जिसमें से वर्तमान में भी करीब 1300 स्कूलों को मान्यता का इंतजार हुआ था। इंटिग्रेटिड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस दाखिल किया था। सोसायटी की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट में केस दाखिल किया।

अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में दाखिला अब 12 तक

अंबाला। अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं (स्नातक) के लिए कालेजों में दाखिला तिथि को 12 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। कालेजों की तरफ से उच्चतर शिक्षा निदेशालय (डीजीएचई) को लिखा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि कालेजों में अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं की सीटें अभी भी खाली होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। दूसरी तरफ पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिला आवेदन की तिथि भी बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है। विभिन्न कालेजों में अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में दाखिला की प्रक्रिया 7 सितंबर से चल रही है। विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जबकि मेरिट लिस्ट और ओपन मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी सभी कालेजों में कई सीटें खाली रह गई।

सावधान : धुंध ने दी दस्तक, संभल कर चलें हाईवे पर, हादसों का खतरा बढ़ा

अंबाला। सीजन की पहली धुंध ने दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में यह धुंध और खतरनाक होगी। सबसे बड़ा खतरा अंबाला-जगाधरी हाईवे पर पसरा हुआ है, जिसे साहा तक चौड़ा किया जा रहा है। कई जगह से इसे खोदा गया है। धुंध भरे सीजन में यह हाईवे काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी ओर अंबाला में डेंजर जोन इस धुंध में खतरा से खाली नहीं होगा। जरा सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। पुलिस का दावा है कि वाहनों पर जहां रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, वहीं वन विभाग से भी ऐसे पेड़ों को कटवाने को कहा गया है, जो सड़कों की ओर झुके हैं और कभी भी खतरा बन सकते हैं।

इस तरह से धुंध करेगी परेशान

मौसम विभाग की मानें, तो आने वाले दिन धुंध भरे हो सकते हैं। इस कारण से हाईवे पर चलने वाले वाहनों को सावधानी बरतनी होगी। अनुमान है कि दस दिसंबर को आसमान साफ रहेगा, जबकि 11 व 12 दिसंबर को आसमान में बादल छाने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बारिश की भी संभावनाएं बन रही है। ऐसी स्थिति में धुंध जहां परेशान करेगी, वहीं ठंड भी और बढ़ेगी। सुबह व रात के समय गहरी धुंध का अनुमान लगाया जा रहा है।

हादसों में जान गंवा चुके हैं लोग

बीते तीन सालों में हुए हादसों में सैंकड़ों लोग जहां अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं कई घायल हो चुके हैं। साल 2018 में जहां 570 हादसे हुए, वहीं इन में 275 लोगों की मौत हो गई, वहीं 453 घायल हुए हैं। इसी तरह साल 2019 में 481 हादसे हुए, जिनमें 245 की मौत हुई, जबकि 390 लोग घायल हुए। इसी तरह साल 2020 (अक्टूबर तक) में 352 हादसे हुए, वहीं इन में 181 लोगों की मौत हुई, जबकि 283 घायल हुए हैं।

यहां पर हादसों का खतरा

जिला में कई ऐसे प्वाइंट हैं, जहां पर हादसों का खतरा सबसे अधिक है। इसके तहत अंबाला कैंट, शास्त्री कालोनी एनएच पर ट्रैफिक कट, इंदिरा चौक व ओवरब्रिज शामिल हैं। इसी तरह अंबाला शहर में जंडली पुल, पॉलीटेक्निक चौक, अग्रसेन चौक, मानव चौक, मटहेड़ी शेखां चौक व कालका चौक पर हादसों का खतरा है। इसके अलावा मुलाना ब्लाक में दोसड़का-बराड़ा बंसल पैलेस के सामने, एमएम रोड पर होली मार्ग, जगाधरी-मुलाना पर एमएम मोड़, अधोया चौक, कालपी चौक व धीन चौक, बराड़ा ब्लाक में त्रिवेणी चौक, साहा ब्लाक में मेन चौक साहा, नारायणगढ़ ब्लाक में शहजादपुर मोड़, बस स्टैंड के पास, डैहर गांव के पास सढौरा रोड पर, बपौली रोड पर बख्बुआ गांव तथा शहजादपुर ब्लाक में एनएच-72 पर टी प्वाइंट, नारायणगढ़ मोड़, पीडब्ल्यूडी कार्यालय के नजदीक तथा मुख्य बस स्टैंड के पास। वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगा कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाईवे पर जहां पर भी खतरा या कमी दिखाई दे रही है, वहां पर काम किया जा रहा है।

फरीदाबाद : बेसहारा बच्ची को मिला इटली दंपत्ति का साथ, दिलाई अपने देश की नागरिकता

फरीदाबाद। करीब चार साल की उम्र में पिता की मौत के बाद मां का मानसिक रूप से दिव्यांग हो जाना, ऐसे में इतनी छोटी बच्ची के भविष्य का क्या होगा, यह सोचकर भी डर लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ बल्लभगढ़ बस अड्डे के पास एक चार वर्षीय बच्ची वैष्णवी के साथ। हालात ऐसे हो गए कि बच्ची की मां ही इसे पत्थरों से पीटने लगी। कुछ दिन बाद मां की भी मृत्यू हो गई, लेकिन किस्मत देखो आज जिस बच्ची का भविष्य के बारे में लोग तरह-तरह की बातें करते थे, आज वही बच्ची इटली की नागरिक बन गई है। बेचारी बच्ची को तो खैर क्या पता होगा, लेकिन भगवान ने उसके लिए कुछ अलग ही सोचा हुआ था। इटली के दंपती ने बच्ची को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गोद ले लिया है।

बालग्राम में रही एक साल

29 अप्रैल 2019 को बल्लभगढ़ बस अड्डे के पास एक महिला चार साल की बच्ची को पत्थरों से पीट रही थी। बेचारी बच्ची बिलख रही थी। आसपास के लोगों से यह नहीं देखा गया। जैसे-तैसे बच्ची को महिला के चंगुल से छुड़ाया और पुलिस को सूचित किया। बाद में पता लगा कि यह महिला बच्ची की मां है, जो पति की मौत के बाद मानसिक रूप से दिव्यांग हो चुकी है। पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड लाइन की मदद से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया। वहां से बच्ची को एसओएस बालग्राम भेज दिया गया। वहां बच्ची करीब एक साल रही। इसके बाद बच्ची मिरेकल सोसायटी के पास आ गई। यहां बच्ची की जानकारी सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर डाली गई। यहां जानकारी देख इटली के एक दंपती ने बच्ची को गोद लेने की इच्छा जताई और आवेदन किया।

भाषा समझने के लिए रखा ट्रांसलेटर

इटली के दंपती बच्ची को गोद लेने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन बच्ची की भाषा कैसे समझी जाए, यह मुश्किल था। जिला बाल संरक्षण इकाई की अधिकारी गरिमा सिंह, चेयरमैन श्रीपाल करहाना, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनीता, मिरेकल चैरिटेबल सोसायटी की परियोजना निदेशक सिमरन और सलाहकार अपर्णा ने आपस में चर्चा की। इसके बाद दंपती ने सुझाव दिया कि वह बच्ची की भाषा समझने के लिए ट्रांसलेटर रखेंगे। इसके बाद बच्ची को 10 नवंबर को दंपती को सौंप दिया गया। दंपती ने अब फोन कर अधिकारियों को सूचित किया है कि बच्ची को इटली की नागरिकता भी मिल गई है। यह सुनकर सभी अधिकारियों को खुशी हुई। जिला बाल संरक्षण इकाई अधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि अब बच्ची का भविष्य संवर जाएगा।

सरकारी कार्यालयों में छुट्टी का माहौल

अंबाला शहर। लघु सचिवालय, 11 बजकर 44 मिनट। आधार कार्ड सेंटर पर लॉक लगा हुआ है। पहले के मुकाबले हलचल भी नहीं के बराबर है। इसी सेंटर के ठीक सामने सरल केंद्र के बाहर भी लोगों की कतार मंगलवार को दिखाई नहीं दी। पहले सरल केंद्र में जाने के लिए बाहर लोगों की कतार लग जाती है। ऐसा ही कुछ हाल लघु सचिवालय में देखने को मिला। जिसमें लोगों का सरकारी कार्यालय में आना न के बराबर रहा। जिस कारण सरकारी कार्यालयों में छुट्टी सा माहौल बना रहा। आधार कार्ड सेंटर पर लॉक लगा रहा। पूछने पर पता चला कि बंद के कारण लोग अपने घरों में ही रहे। आधार कार्ड को लेकर सेंटर में पहुंचे ही नहीं। पता चला कि आधार कार्ड अपडेट करने वाले सुबह पहुंचे थे, परंतु लोगों के न आने के कारण सेंटर को बंद कर चले गए।

फल व सब्जियों में कीटनाशक व फर्टिलाइजर की होगी जांच, 1.94 करोड़ की लागत से सिरसा में स्थापित की लैब

सिरसा। ऑर्गेनिक फलों व सब्जियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिरसा में एक करोड़ 94 लाख रुपये की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला बनाई गई है। यह प्रयोगशाला राज्य की दूसरी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है। सरकार द्वारा एक प्रयोगशाला करनाल जिले के घरोंड़ा में भी स्थापित की गई है। कोरोना काल के चलते प्रयोगशाला में अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही जांच कार्य शुरु हो जाएगा जिससे किसान प्रयोगशाला की सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

फल व सब्जियों में फर्टिलाइजर व पेस्टिसाइड का पता चल सकेगा

प्रयोगशाला का उद्देश्य फल व सब्जियों के नमूने में कीटनाशक अवशेषों की उपलब्धता की जांच, कीटनाशक अवशेषों की मॉनिटरिंग के साथ-साथ किसानों को कीटनाशक दवाओं का समुचित उपयोग व प्रबंधन के लिए जागरूक करना है। किसानों को उनके फल व सब्जियों में प्रयोग किए जा रहे फर्टिलाइजर व पेस्टिसाइड के मात्रा का पता चलेगा। खेती में कीटनाशकों व रासायनिक खादों की होड़ पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रयोगशाला स्थापित की गई है। प्रयोगशाला से कोई भी व्यक्ति अपने खेत की मिट्टी व पानी की जांच के साथ-साथ बागवानी की फसलों में प्रयोग होने वाली खाद व दवाई के पैमाने की जांच भी करवा सकता है।

आधुनिक मशीनों से फल, सब्जियों में पेस्टिसाइड की होगी जांच

प्रयोगशाला के इंचार्ज साधुराम झोरड़ ने बताया कि कोविड-19 के चलते इस लैब में अभी कार्य शुरु नहीं हुआ है। तकनीकी स्टॉफ की तैनाती हो चुकी है और जल्द ही प्रयोगशाला में काम शुरु हो जाएगा। इस आधुनिक प्रयोगशाला में रोटरी वैक्यूम इवपोरटर, एचपीएलसी, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमिटर, लमीनार फ्लो कैबिनेट, लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज, मुफ्फ्ले फर्नेस, हॉट एयर ओवन व डीप फ्रीजर मशीनें स्थापित है। उन्होंने बताया कि फसलों में बहुत अधिक फर्टिलाईजर, पेस्टिसाइड आदि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है। जोकि न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म करता है, वहीं कैंसर जैसी भयानक बीमारियों में सहायक हो रहा है।

परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी अपना कर आमदनी बढ़ा सकते हैं किसान

उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि इस प्रयोगशाला की मदद से किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा कर अन्य फसल विविधिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। किसान गेहूं, धान, कपास जैसी परंपरागत खेती से न तो अधिक उत्पादन ले सकता है और न ही अधिक मूल्य लिया जा सकता है। इसके साथ-साथ आधुनिक खेती, बागवानी व अन्य खेती से जुड़े व्यवसाय को अपनाकर अपने आय में बढ़ोतरी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बीती 6 जनवरी को इस प्रयोगशाला को जिला के किसानों को समर्पित किया था।